रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

शनिवार
26 सितंबर -2026
वर्ष 11, अंक 18
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

पेज-8

संक्षिप्त समाचार

भारत का चीनी संकट और ज्यादा गहराया

- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर के लिए इंपोर्ट की आई नौबत

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है। करीब एक दशक तक वह सरप्लस की स्थिति में रहा है लेकिन, देखते ही देखते अचानक हालात बदल गए हैं। भारत में चीनी संकट गहराता दिख रहा है। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि भारत को लगातार दूसरे साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्यों में पानी की भारी कमी से

चीनी की रिकवरी घटने और प्रोडक्शन में कमी और बढ़ने का खतरा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। यह लगभग एक दशक तक चीनी के मामले में सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन वाला रहा था। हालांकि, कम प्रोडक्शन के कारण घरेलू कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसे 2025-26 सीजन में चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में लंबे समय से बारिश की कमी है। राज्यों की ओर से सिंचाई के बजाय पीने के पानी के लिए रिजर्वायर के पानी को प्राथमिकता दी गई।

समाज के लिए काम करें, वोटबैंक की राजनीति के लिए नहीं

- पीएम मोदी ने वाराणसी से वडनगर जा रहे बाइकर्स से बात की

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के जीवन की ओर देखते हैं, तो वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और आजादी का आंदोलन चलाने के साथ-साथ एक बड़े सामाजिक सुधारक भी थे। समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ उन्होंने हमेशा काम किया। इसलिए हमें

भी समाज में निरंतर सुधार और सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करते रहना चाहिए, केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए नहीं। दरअसल, दो बाइक रैलियों को 17 सितंबर को पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर रवाना किया गया था। एक रैली उनके जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से वडनगर के लिए निकली है। दोनों यात्राएं 7 अक्टूबर को पूरी होंगी। ये रैलियां मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करने के लिए निकाली जा रही हैं। बीते 12 साल में भारत में शहरों और गांवों के बीच जो गैप था, वह काफी कम हुआ है। आज गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। हमारी बहनों और बेटियों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

गणपति अपने गाँव चले...

अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ विदा हुए बप्पा

बप्पा को विदा करते वक्त नम हुई श्रद्धालुओं की आंखें

नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार को गणेश उत्सव का आखिरी दिन रहा। देशभर में गणेश प्रतिमाओं का नदियों, तालाबों, झीलों और कृत्रिम कुंडों में विसर्जन किया गया। मुंबई में 25 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। विसर्जन के लिए 383 कृत्रिम कुंड भी बनाए गए थे। हैदराबाद में भी 25-30 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आए। निगरानी के लिए 24 ड्रोन और 10 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हुसैन सागर के आसपास 100 अतिरिक्त कैमरे, जबकि झील किनारे क्रेन, इमरजेंसी बोट, गोताखोर और मेडिकल पोस्ट तैनात किए गए थे। जुलूसों के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन और कई पाबंदियां लागू रहीं। एजेंसी के अनुसार, इस साल अब तक 12 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान डेढ़ दिन, पांच दिन, छह दिन और सात दिन की अवधि में 1,63,386 गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर में 1.65 लाख से ज्यादा घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

हैदराबाद में 39 लाख में बिका एक गणेश लड्डू

गणेश चतुर्थी के मौके पर हैदराबाद में शुक्रवार को भव्य जुलूसों और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। इसी बीच शहर में गणेश लड्डू प्रसाद की पारंपरिक नीलामी भी चर्चा में रही। इस साल बालापुर गणेश का लड्डू 39 लाख रुपये में नीलाम हुआ। बालापुर गणेश की लड्डू नीलामी हैदराबाद में गणेश उत्सव की सबसे चर्चित परंपराओं में से एक है। इस साल समा प्रणीत रेड्डी ने 39 लाख रुपये की बोली लगाकर लड्डू अपने नाम किया। यह रकम पिछले साल के मुकाबले 4 लाख रुपये अधिक है। यह नीलामी 25 सितंबर को सुबह साढ़े 9 बजे आखिरी पूजा और गांव में जुलूस के बाद आयोजित की गई। नीलामी में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी का इतिहास करीब तीन दशक पुराना है।

प्रतिशोध में फंसाया गया पुत्र ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू न्याय के लिए एसपी-डीसी के दरबार पहुंचीं विद्यावती देवी

लाइसेंस और गोली की जांच से होगा खुलासा

दैनिक अलग पहचान, अन्नपूर्णा गुप्ता, मुख्य संपादक, नई दिल्ली/

झारखंड के औद्योगिक जिला बोकारो बीएस सिटी थाना कांड संख्या 206/2026 को फर्जी बताते हुए विद्यावती देवी ने दिनांक 25 सितंबर 2026 को बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा और उपायुक्त के चिट्ठी को लेकर शताब्दी मजूमदार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि एसपी साहब और एसडीओ मैडम को सूचना देने के प्रतिशोध में रितेश सिंह ने उनके पुत्र ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू साव पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू साव ने 18 सितंबर को लिखित पत्र में विश्वकर्मा पूजा के नाम पर हथियार प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग और अगले दिन शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डीजे पर रात्रि में नर्तकी नचाने का आरोप लगाया और यादव समाज

पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा (भा0 पु0 से0) (तस्वीर)

के लोगों से सदर अस्पताल में मिलकर रितेश सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रतिशोध में गिरिडीह के पूर्व प्रत्याशी ज्ञानेश्वर प्रसाद को झूठा आरोप लगाते हुए मुख्य आरोपी बनाया गया है।

रितेश सिंह के कथित अवैध कार्यालय में रितेश सिंह गिरोह के सदस्य दीपक मुर्मू ने अपने फेसबुक अकाउंट से 13 से 14 हथियारों की पूजा की जो तस्वीरें वायरल किया है, उनकी गहन जांच हो। बोकारो

दीपक मुर्मू के फेसबुक से वायरल हथियार पूजा का स्क्रीनशॉट (तस्वीर)

पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल 13 हथियारों के लाइसेंस, अनुमत गोली, स्टॉक पंजी और बैलिस्टिक जांच निष्पक्ष करने की आवश्यकता है रितेश सिंह के फेरारी के बाद मामला का लीपा होने की आशंका लग रही है।

बताया गया कि रितेश सिंह पर पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने अपने मित्र अमित कुमार सिंह के माध्यम से गुड्डू साव को प्रतिशोध में फंसाया है और पुलिस के साथ सांठगांठ कर झूठी गवाही दिलवाने का प्रयास कर रहा है। कांड संख्या 206/26 में रितेश सिंह के मित्र अमित कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि गुड्डू ने 19 सितंबर की सुबह 3:30 बजे 10-15 लोगों के साथ जान मारने की नीयत से अपहरण का प्रयास किया, जबकि गुड्डू 18 सितंबर की रात 10:22 बजे अपना घर प्रवेश करने की बात सामने आई है। दरअसल मामला चाय गिरने से शुरू हुआ था। गौतम यादव की चाय रितेश सिंह पर गिरने के बाद रितेश और उसके लोगों ने गौतम और जितेंद्र यादव के साथ बेरहमी और अन्य से मारपीट कर हथियार के बल पर गाड़ी में उठा लिया और सोने की चेन-अंगूठी छीन ली।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उठे सवालों का जवाब जरूरी; 13 करोड़ से अधिक नामों के मामले में सुप्रीम कोर्ट करे जांच - इन्तेखाब आलम

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची/

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इन्तेखाब आलम ने कहा है कि देश में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे गंभीर सवालों पर अब केवल राजनीतिक बहस पर्याप्त नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच की आवश्यकता है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्क्र) के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। वहीं, चुनाव आयोग के दो आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले दस महीनों में कम-से-कम 14 बार आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इन्तेखाब आलम ने कहा कि जब बिहार से शुरू हुई स्ढ्क्र प्रक्रिया बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों मतदाताओं को प्रभावित कर रही हो और उसी समय आयोग के भीतर से ही निर्णय लेने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां सामने आएं, तो देश को इसका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से स्पष्ट जवाब की मांग की कि यदि आयोग के सभी निर्णय पूरी तरह पारदर्शी और नियमसम्मत थे, तो उनके ही दो सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने बार-बार लिखित आपत्तियां क्यों दर्ज कीं? रिपोर्ट में कुछ कदमों को 'unauthorised' और 'illegal' बताए जाने का भी उल्लेख है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसी राजनीतिक दल के हित के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय के मताधिकार और चुनाव आयोग की संवैधानिक विश्वसनीयता की रक्षा के लिए है। मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम रहना या हटना सीधे उसके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा विषय है। इन्तेखाब आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे घटनाक्रम का गंभीरता से संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच की निगरानी करनी चाहिए। जांच के दौरान यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी के देश से बाहर जाने की वास्तविक आशंका हो तो कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि जांच प्रभावित न हो और कोई व्यक्ति जवाबदेही से बच न सके। उन्होंने जोर दिया कि यह समय केवल बयानबाजी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। चुनाव आयोग देश की चुनावी व्यवस्था का प्रहरी है; इसलिए उसकी निष्पक्षता पर उठे सवालों का जवाब भी उतनी ही पारदर्शिता से मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन मतदाता का अधिकार और संविधान स्थायी हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और महाराष्ट्र तक मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कांग्रेस का आंदोलन इसी संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए जारी रहेगा।

जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग-चत्र से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश

- आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत होंगे उत्तरदायी

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची/

रांची। भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कल दिनांक 26.09.2026 को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग-

चत्र से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड, राँची के विशेष बुलेटिन दिनांक 25.09.2026 को भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में येलो जोन की श्रेणी में राँची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उक्त अवधि में ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो उनके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे। यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि भारी बारिश के कारण होने वाली संभावित परेशानियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

देश में अब आ रही हैं 100 फीसदी इथेनॉल वाली गाड़ियां

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा-ई-20 पेट्रोल से बढ़े हैं गाड़ियों में माइलेज
- बसों पर नितिन गडकरी ने कहा-नोट लेकर आरटीओ अफसर ठपठपा देते हैं

भोपाल (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। भोपाल में सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत के दौरान उन्होंने ई-20 पेट्रोल को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही बसों की रजिस्ट्रेशन को लेकर आरटीओ पर तंज कसा है। साथ ही नितिन गडकरी ने प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी में चलाने के लिए नियम बनाने की मांग की है। दरअसल, बीते कुछ दिनों से ई-20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। इसे लेकर लोगों के बीच में ई-20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी ने बात की है। उन्होंने कहा कि ई-20 का मतलब है कि हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाते हैं, यह किसान तैयार करता है। यह 19 देशों में है। अमेरिका, जर्मनी

और जापान जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 2022 से 4 करोड़ फोर व्हीलर में ई-20 पेट्रोल डाला जाता है। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है। इसकी वजह से गाड़ियों के एवरेज भी बढ़े हैं। अब किसान अन्नदाता नहीं, उर्जादाता है। फिर दूसरा यह आया है कि 100 फीसदी इथेनॉल हमने गाड़ी में डाला है, इसे फ्लेक्स इंजन कहते हैं। गाड़ी में 100 फीसदी इथेनॉल डालने पर जब गाड़ी चलती है तो उसमें 60 फीसदी बिजली उत्पन्न होती है। पेट्रोल की तुलना में उससे एवरेज अधिक मिलता है।

हाइड्रोजन बस और ट्रक चलाने का प्लान- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे यहां इसी से खेती हो रही है। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी से घूमता हूं। पानी से हाइड्रोजन तैयार होता है। हिंदुस्तान में 10 रूट पर अब हाइड्रोजन से चलने वालीं बसें और ट्रक शुरू करने जा रहे हैं।

गांधी जी लेकर ठप्पा मार देते हैं

उन्होंने कहा कि आरटीओ के अफसर इस बात का ध्यान रखें। मुझे मालूम नहीं लेकिन बहुस से आरटीओ के ऑफीसर गांधीवादी हैं। गांधी की नोट दिखती है तो ठपा ठप ठपठपा देते हैं। इसके बाद सभी लोग हंसते हैं। वह याद दिलाते हैं कि गलत बस को सैंक्शन किया तो सबकी नौकरी जाएगी।

बिहार सीएम ने पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की, बाद में की डिलीट

तेजस्वी बोले-सीएम पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे

पटना (एजेंसी)। बिहार के जमुई में सड़क पर बदसलूकी की पीड़ित के परिवार के फोटो शेयर करने पर विवाद हो गया है। पीड़ित परिवार गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला था। सम्राट चौधरी ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स हैंडल से बिना ब्लर किए शेयर कर दी। 15 मिनट बाद इसे डिलिट कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग कर दी है। राजद सांसद मीसा भारती ने भी इस पोस्ट पर सवाल उठाए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित बच्ची की मां ने सीएम से मिलने के बाद कहा, हमें बेटी के साथ हुई घटना का दर्द अब भी है, लेकिन कार्रवाई होने और सरकार से सुरक्षा को लेकर मिले

आश्वासन से राहत मिली है। पीड़ित की मां ने बताया, 24 सितंबर की शाम हम पटना आए।

गोड्डा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

साजिद,राज्य ब्यूरो चीफ,झारखंड प्रदेश/

गोड्डा:नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गुलजारबाग सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी में अशोक कुमार के घर से 11.5 ग्राम ब्राउन शुगर, 77,220 रुपये नकद, 7 मोबाइल, लैपटॉप और तौल मशीन बरामद हुई। वहीं आनंद कुमार झा से 7.2 ग्राम और अंकित अग्रवाल उर्फ गोलू से 4.2 ग्राम ब्राउन शुगर मिली। मोहन कुमार साह भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोड्डा पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।

एसबीयू में मनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांची।सरला बिरला विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एसबीयू के महानिदेशक प्रो गोपाल पाठक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी से सीख लेने का आह्वान करते हुए उनकी ईमानदारी और सादगी की चर्चा की। उन्होंने पंडित जी की जीवनी को ही अपने आप में दर्शन करार देते हुए कहा कि अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका सिद्धांत अतुलनीय और आज के संदर्भ में भी व्यावहारिक है। कुलपति प्रो सी जगनाथन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संघर्षशील व्यक्तित्व पर बात करते हुए समाज और देश के प्रति उनके समर्पण को अविस्मरणीय बताया। अंत्योदय पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सेवा की भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में कुलसचिव प्रो श्रीधर दंडीन, प्रो वी के सिंह एवं अमित चरण ने भी दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी और उनके दृष्टांतों पर अपना विचार प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर विवि परिवार के सभी शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

सरला बिरला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान एवं राज्यसभा सांसद सह निदेशक, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉ प्रदीप कुमार वर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

एनएचएम के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए स्किल टेस्ट संपन्न

▶ उप विकास आयुक्त ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची,

धनबाद।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के स्किल टेस्ट का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा हॉल, कंप्यूटर लैब, बायोमेट्रिक, दस्तावेज़ सत्यापन तथा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। उप विकास आयुक्त ने परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एएनएम, स्टाफ नर्स, ब्लॉक डेटा मैनेजर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट (आरबीएसके), फार्मासिस्ट (आयुष), वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर, लैबोरेट्री तकनीशिन, ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर, सीनियर ट्रीटमेंट लैबोरेट्री सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर सहित कुल 12 श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट का आयोजन किया गया था। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए केंद्र पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरी परीक्षा प्रक्रिया कड़ी निगरानी में संपन्न हुई।

मिलावटी पनीर व खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

गौतम डेयरी सील, भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री जब्त

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस क्रम में आज सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने धनबाद शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से पनीर के नमूने एकत्र कर रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, रांची भेजे गए। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध पाए गए पनीर व अन्य उत्पादों को मौके पर जब्त किया गया।

निरीक्षण दल के स्टील गेट स्थित गौतम डेयरी पहुंचने पर उसका संचालक दुकान छोड़कर फरार हो गया। जांच में प्रतिष्ठान का एफएसएसएआई लाइसेंस भी एक्सपायर्ड (अवैध) पाया गया। दुकान से 48 किग्रा संदिग्ध पनीर, 2 किग्रा घी तथा खोवा जब्त किया गया। भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने और संचालक के भागने के कारण दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं पुलिस लाइन स्थित राकेश डेयरी से 10 किग्रा संदिग्ध पनीर जब्त किया गया।

इसके अलावा टीम ने अन्य प्रतिष्ठानों से भी नमूना संग्रहण किया। इसमें सरायढेला स्थित रूफ़ 709, निर्मल स्वीट्स, रमेश डेयरी तथा बरटांड़ स्थित गंगा डेयरी से भी पनीर, घी एवं खोवा मिठाई के नमूने एकत्र किए गए। मौके पर की गई जांच में विफल पाए गए खाद्य पदार्थों को भी जब्त किया गया।

वहीं उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को शुद्ध, स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निरीक्षण अभियान पूरे जिले में निरंतर जारी रहेगा। मिलावटखोरों और बिना वैध लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. राजा कुमार के साथ नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंदन साव, चन्द्रदेव गंझू, जैस्मीन केरकेट्टा, नैना नायक सहित विभागीय कर्मी राहुल कुमार पासवान, राहुल कुमार, अमित कुमार एवं शुभम कुमार उपस्थित रहे।

फोवा का सराहनीय पहल : सरकारी स्कूल के बच्चों को खेल सामग्री व जल सुविधा का सहयोग

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता,राधे /

रांची : फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (फोवा) द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय, कालामाटी, खूंटी में सामाजिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना था।

इस दौरान एसोसिएशन की ओर से विद्यालय को माइक सहित पोर्टेबल स्पीकर, क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन रैकेट और छाता प्रदान किया गया।

विद्यालय में जल संकट को देखते हुए फोवा की सचिव भारती कुमार ने निजी पहल पर पानी का पंप भी दान किया।

इस अवसर पर फोवा अध्यक्ष भारती कुमार, सचिव नीमा ल्हाकी भूटिया, संयुक्त सचिव मीनू पंडियन, कोषाध्यक्ष रमिता कंबोज और खेल समन्वयक विशाखा वर्मा सहित 20 सदस्य उपस्थित रहीं। सदस्यों ने बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

मोबाइल चोरी के बाद बैंक खाते से 10 हजार रुपये की अवैध निकासी

देवघर। नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ स्थित कैलाशपुरी मुहल्ला निवासी रतना कुमारी का मोबाइल चोरी होने के बाद उनके बैंक खाते से 10 हजार रुपये की अवैध निकासी हो गयी. मोबाइल चोरी होने के बाद उसी नंबर का नया सिमकार्ड जारी कराने पर उन्हें खाते से रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली.जानकारी के अनुसार, रतना कुमारी का मोबाइल फोन 22 सितंबर को चोरी हो गया था. मोबाइल चोरी होने के बाद अज्ञात व्यक्ति ने उनके मोबाइल का इस्तेमाल कर बैंक खाते से 10 हजार रुपये की निकासी कर ली. मोबाइल चोरी होने के कारण रतना कुमारी को तत्काल खाते से हुई निकासी की जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद रतना कुमारी ने नया मोबाइल फोन खरीदा और अपने पुराने नंबर का नया सिमकार्ड जारी कराया. नये मोबाइल में सिमकार्ड इंस्टॉल करने के बाद जब उन्होंने बैंक खाते से संबंधित जानकारी देखी, तो खाते से 10 हजार रुपये निकासी होने का पता चला. खाते से रुपये निकासी की जानकारी मिलने के बाद रतना कुमारी मामले की शिकायत लेकर साइबर थाना पहुंचीं. उन्होंने पुलिस को मोबाइल चोरी होने और इसके बाद बैंक खाते से 10 हजार रुपये निकासी होने की जानकारी दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

विधायक चंद्रदेव महतो के प्रयास लाए रंग: रखीतपुर अंडरपास के पास पाइपलाइन मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

सिंदरी/धनबाद: सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं विधायक चंद्रदेव महतो की सक्रिय पहल और क्षेत्र की जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के संकल्प से एक और महत्वपूर्ण जनहित का कार्य प्रारंभ हो चुका है। रखीतपुर अंडरपास के पास पिछले कुछ समय से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मती का कार्य श्यान कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, जिससे स्थानीय जनता को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने में माननीय प्रमुख पिंकी देवी जी, विधायक प्रतिनिधि हीरालाल मोदक, विधायक प्रतिनिधि सह मीडिया प्रभारी शीतल दत्ता, प्रमुख प्रतिनिधि विजय रजक, मुखिया अंजना कुमारी, विभागीय [एसडीओ (स्छह) एवं विभागीय अभियंता लखिराम मांझी की तत्परता और सामूहिक प्रयास सराहनीय रहे हैं। इन सभी के आपसी समन्वय और तत्परता से ही इस जनहित के कार्य को गति मिली है।

कार्यस्थल पर चल रहे प्रगति का जायजा लेने और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए राधेश्याम रजक, सुनील महतो, कृष्णा दा, विजय राम तपन रजक एवं अन्य सभी सक्रिय सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विधायक के सहयोगियों ने कहा कि हम क्षेत्र के समग्र विकास और जनता की हर छोटी-बड़ी सुविधाओं के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और आगे भी जनसमस्याओं का इसी तरह त्वरित समाधान किया जाएगा।

खैरटाँड़ में छाता मेला महोत्सव-2026 का आगाज, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने किया उद्घाटन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

बलियापुर (धनबाद):खैरटाँड़ आमझर स्थित जेएसी क्लब मैदान में 'छाता मेला महोत्सव-2026' के तहत खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि शीतल दत्ता, भाकपा माले नेता कृष्णा दा, प्रमुख प्रतिनिधि राधेश्याम रजक और विजय रजक मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय कर उत्साह बढ़ाया। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि खेल से शारीरिक विकास और भाईचारा मजबूत होता है। इस दौरान जेएसी क्लब के मोहन हेंब्रम, संजय मुर्मू, विशाल सोरेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व खेल प्रेमी उपस्थित थे।

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह मांग को लेकर बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता, रांची /

रांचीः पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर शुक्रवार को रांची में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय, सुजाता चौक के समीप आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बैंककर्मी शामिल हुए। महिला बैंककर्मियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की भी सहभागिता रही।

प्रदर्शनकारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह तत्काल लागू करने, पीएलआई भुगतान में विसंगतियां दूर करने, पेंशन अपडेशन सहित लंबित मुद्दों का समाधान करने और वित्तीय सेवा विभाग की कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की।

यूनियनों ने कहा कि बैंकिंग उद्योग में 8 मार्च 2024 को हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते के कई मुद्दे अब भी लंबित हैं। इनमें पेंशन अपडेशन और 10 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त बैंककर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का मुद्दा शामिल है। संगठन ने आरोप लगाया कि इन मामलों के समाधान में लगातार देरी की जा रही है।

वक्ताओं ने कहा कि मांगों को लेकर पहले बैज पहनने, धरना और अन्य कार्यक्रमों के अलावा 11 सितंबर को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल की गई थी। वार्ता विफल रहने के बाद अब 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का निर्णय लिया गया है। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगों पर पहल नहीं होने पर 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की जाएगी।

प्रदर्शन में प्रकाश उरांव, कुणाल कुमार, राजेश मुंडा, मनोज कुमार, उज्ज्वल लकड़ा, मनीष कुमार सिंह, शशिकांत भारती, मुनेन्द्र पाण्डेय, एमएल सिंह, एसके पाण्डेय, घनश्याम श्रीवास्तव और सीमा कुमारी समेत अन्य ने विचार रखे। यूनियन ने आम जनता, बैंककर्मियों, किसानों, मजदूरों, छात्रों और युवाओं से आंदोलन को सहयोग देने की अपील की।

28 से तीन दिवसीय हड़ताल

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक

दैनिक अलग पहचान, डेस्क संवाददाता,

▶ जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक
▶ योजनाओं की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन पर विशेष जोर
▶ नियमित स्थल निरीक्षण करते हुए कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी का निर्देश
▶ मॉडल विलेज के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश

रांची।जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन (JJM) एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची संजय भगत, जिला शिक्षा पदाधिकारी बादल राज, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल रांची पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जल जीवन मिशन की प्रमंडलवार प्रगति की समीक्षा की। पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों प्रमंडलों में संचालित MVS (Multi Village Scheme) एवं SVS (Single Village Scheme) के कार्यों की स्थिति एवं लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

योजनाओं की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन पर विशेष जोर

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त ने सभी सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने नियमित स्थल निरीक्षण करते हुए कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी करने को कहा।

उन्होंने योजनाओं से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन को अद्यतन रखने तथा कार्यों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। JJM के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ SVS क्लस्टर प्रोग्रेस की भी समीक्षा की गई। संबंधित छ्श्वह्य एवं अभियंताओं को स्थल पर जाकर योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

SBM-G के तहत IHHL निर्माण की प्रगति की समीक्षा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) निर्माण की प्रखंडवार स्थिति की जानकारी ली गई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त ने पात्र लाभुकों का शीघ्र चयन करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लाभुकों के चयन की प्रक्रिया में ऑनलाइन माध्यम के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया।

मॉडल विलेज के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

बैठक में मॉडल विलेज की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शेष गांवों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यों को और बेहतर बनाने तथा लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मॉडल विलेज के रूप में विकसित किए जा रहे गांवों में सभी आवश्यक कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के बाद उसका स्थल पर सत्यापन सुनिश्चित करने तथा कमियों को चिह्नित कर तत्काल सुधार कराने का निर्देश भी दिया गया।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

संक्षिप्त समाचार

पलामू करमा पूजा हादसा : गढ़वा से लापता बच्चे का शव बरामद, कुल पांच बच्चों की हुई मौत

पलामू, एजेंसी। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा के दौरान नदी में लापता हेमंत कुमार नामक बच्चे का शव बरामद हो गया है. हेमंत कुमार का शव गढ़वा के बेलचंपा इलाके से मिला है. बुधवार को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा के विसर्जन के दौरान हादसा हुआ था. करम डाल का विसर्जन करते समय कोयल नदी में पांच लड़के डूब गए थे. चार लड़कों के शव घटनास्थल से दो किलोमीटर के दायरे में बरामद कर लिए गए थे. पांचवें लड़के हेमंत कुमार का शव करीब 48 घंटे बाद गढ़वा के बेलचंपा इलाके से मिला है. पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में तलाशी अभियान के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया था. एनडीआरएफ की टीम गुरुवार से ही हेमंत कुमार को खोजने के लिए तलाशी अभियान चला रही थी. शुक्रवार को पुलिस और एनडीआरएफ के संयुक्त अभियान में हेमंत कुमार का शव बरामद किया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए. शव को नदी की धार से निकाला गया. चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि हेमंत कुमार का शव गढ़वा के बेलचंपा इलाके से बरामद किया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. चैनपुर करमा हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़कर पांच हो गई है. सभी मृतक दोस्त थे और एक ही गांव तथा मोहल्ले के रहने वाले थे. करम डाल के विसर्जन के दौरान एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में ये पांच दोस्त डूब गए थे.

गुमला में तेज रफ्तार बोलेरो का कहर : कुछ दूरी पर दो बाइक-स्कूटी को मारी टक्कर, 1 की मौत

गुमला, एजेंसी। शहर के सिसई रोड में बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो ने कुछ ही दूरी के अंतराल में दो हादसों को अंजाम दिया. पहली घटना में बाइक सवार हेसागुटु, सिसई निवासी महेश महतो की मौत हो गयी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार बोलेरो ने पहले बाइक सवार दोनों युवकों को टक्कर मारी. हादसे के बाद चालक रुकने के बजाय वाहन को तेज रफ्तार में भगाने लगा. कुछ दूरी आगे मदरसा के पास बोलेरो ने पानी लेकर लौट रहे दो भाइयों की स्कूटी को भी जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में लोहरदगा रोड निवासी आदित्य प्रकाश के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी, जबकि चेटर निवासी नैतिक का पैर टूट गया. दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लगातार दो हादसों के बाद स्थानीय लोगों ने बोलेरो का पीछा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में वाहन को पालकोट रोड की ओर लेकर फरार हो गया. देर रात तक बोलेरो और उसके चालक का पता नहीं चल सका था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस बोलेरो की पहचान करने और फरार चालक की तलाश में जुटी है.

अरगोड़ा चौक के पास बंद होटल में लगी आग, 3.5 करोड़ का नुकसान

रांची, एजेंसी। अरगोड़ा चौक स्थित आनंद टावर के चौथे तल्ले पर संचालित होटल-सह-रेस्तरां में मंगलवार की देर रात भीषण आग लग गयी. आग लगने से होटल का इंटीरियर, किचन के उपकरण और फर्नीचर जलकर नष्ट हो गये. घटना को लेकर संचालक ने करीब 3.5 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है. थाने में दिये गये आवेदन के अनुसार रातू के निमेट पावर हाउस निवासी महेश महतो का एम बार एंड रेस्टोरेंट पिछले सात माह से बंद था. मंगलवार की रात करीब 11:20 बजे प्रतिष्ठान से अचानक आग की लपटें उठती दिखीं. आग लगने की सूचना तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गयी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. संचालक के अनुसार आग लगने से प्रतिष्ठान का इंटीरियर, किचन में लगे उपकरण और फर्नीचर पूरी तरह जल गये. उन्होंने शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जतायी है. अरगोड़ा थाना पुलिस ने सनहा दर्ज कर लिया है. पुलिस आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कर रही है.

जमीन घोटालों की जांच के बीच बड़ा फेरबदल, एक साथ हटाये गये 3 डीएसपी

रांची, एजेंसी। पूर्व डीजी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल में जमीन घोटालों और भूमि विवादों की जांच के लिए गठित एसआइटी अब अफसरों की कमी से जूझ रही है. एसआइटी में तैनात तीन डीएसपी को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है. 21 सितंबर को जारी आदेश के तहत डीएसपी सुमनागिनी नाग और तारामणि बारखला को जैप-10, होटवार, जबकि डीएसपी प्रदीप पॉल कच्छप को झारखंड एटीएस वापस भेजा गया है. तीनों डीएसपी की एसआइटी में तैनाती 12 अगस्त 2024 को हुई थी. एसआइटी में जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच चल रही थी. जांच के दौरान कुछ मामलों को लेकर विवाद भी सामने आये. इसके बाद जांच की रफ्तार प्रभावित हुई और धीरे-धीरे कई मामलों की जांच लगभग ठंडे बस्ते में चली गयी.तीनों डीएसपी की वापसी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गयी थी. सीआइडी एडीजी मनोज कौशिक ने 27 मई 2026 को पुलिस मुख्यालय से तीनों डीएसपी को उनके पैतृक विभाग में वापस भेजने का आग्रह किया था. करीब चार महीने बाद इस पर कार्रवाई करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गयी. एसआइटी के तीनों डीएसपी के हटने के बाद जमीन घोटालों और भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों की जांच की दिशा और रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं. खासकर उन मामलों में, जिनकी जांच पहले ही धीमी पड़ चुकी थी.

झारखंड की जेलों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत,

आठ हफ्ते में होंगे रेगुलर

रांची, एजेंसी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों में संविदा और दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 23 सितंबर 2026 को कई याचिकाओं पर साझा फैसला सुनाते हुए 23 नवंबर 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत जेलों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लेने का निर्णय किया गया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेलों में काम कर रहे हैं और कई कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं. याचिकाकर्ता लक्ष्मीकांत गुइन की नियुक्ति 19 जून 2013 को तेनुघाट उपजेल में चालक के पद पर दैनिक वेतनकर्मी के रूप में हुई थी. रिकॉर्ड के अनुसार वह पद स्वीकृत और स्थायी पद था.

कोर्ट ने 3 मार्च 2021 के राज्य सरकार के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया. इसमें हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों के आधार पर 183 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गयी थीं. ये कर्मचारी मुख्य रूप से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत थे. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता भी लंबे समय से स्वीकृत पदों पर काम कर रहे हैं और समान परिस्थितियों में उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए.

अदालत ने पाया कि 23 नवंबर 2021 को जेल महानिरीक्षक की ओर से आउटसोर्सिंग के जरिए सेवाएं लेने का निर्देश दिया गया था. वहीं, रिकॉर्ड में 19 दिसंबर 2022 की एक फाइल नोटिंग से पता चलता है कि प्रशासनिक विभाग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति को लेकर कोई नीति तय नहीं की थी. कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी कोई नीति ही नहीं थी,

तो अधिकारियों की ओर से इस तरह का निर्णय लेना निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था.

कोर्ट ने जेलों को संवेदनशील संस्थान बताते हुए कहा कि ऐसे स्थानों पर कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार का पर्याप्त नियंत्रण जरूरी है. आउटसोर्सिंग की स्थिति में कर्मचारियों पर नियंत्रण संबंधित एजेंसी का होगा. अदालत के अनुसार गंभीर कदाचार की स्थिति में सरकार के सामने नियंत्रण और कार्रवाई से जुड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है. इसलिए स्वीकृत पदों पर जेलों में आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति को कोर्ट ने मनमाना और अवैध माना.

अदालत ने नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए लगातार अनियमित या आउटसोर्स नियुक्तियों का सहारा नहीं लेना चाहिए. कोर्ट ने यह भी माना कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों की स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने 23 नवंबर 2021 के आदेश और उसके आधार पर लिए गए अन्य फैसलों को रद्द कर दिया. याचिकाकर्ताओं को पहले की तरह संविदा या दैनिक वेतन पर काम करते रहने और उसी आधार पर वेतन पाने का अधिकार दिया गया. साथ ही राज्य सरकार को 183 नियमित कर्मचारियों के समान स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया.

अदालत ने राज्य सरकार को स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से रोक दिया. 22 सितंबर 2022 को पारित अंतरिम आदेश को भी कोर्ट ने अंतिम रूप से लागू कर दिया. इस फैसले के बाद झारखंड की जेलों में लंबे समय से संविदा और दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खुल गया है.

गिरिडीह हत्या मामला: आजसू छात्र संघ का उपाध्यक्ष है आरोपी सतीश यादव, जिलाध्यक्ष समेत 8 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ

गिरिडीह, एजेंसी। डुमरी-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बंदरकुप्पी के समीप एएसआई के बेटे की हत्या के बाद एसपी डॉ. बिमल कुमार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है. सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के नेतृत्व में जांच दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, स्पेशल सेल के मणिकांत की टीम ने छापेमारी की है. अभी इस मामले में लगभग 6 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है. जिनसे पूछताछ हो रही है, उनमें मैगी बेचने वाले दुकानदार के साथ-साथ आजसू छात्र संघ से जुड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है.

इधर, बताया जाता है कि हत्याकांड में जिस सतीश यादव का नाम आया है, वह पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह का रहने वाला है. सतीश पिछले दिनों तब चर्चे में आया था जब आजसू छात्र संघ की जिला कमेटी का पूर्णगठन किया गया था.

जानकारी के अनुसार, सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. ऐसे में पुलिस आजसू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अक्षय यादव को भी थाना लायी है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.

अक्षय से सतीश के संदर्भ में पूछताछ की गई है. अक्षय ने बताया है कि सतीश आजसू छात्र संघ का जिला उपाध्यक्ष है. दूसरी तरफ सतीश समेत इस घटना में शामिल अन्य लोगों की खोज भी लगातार हो रही है. एक टीम सतीश को खोजने निकली है. इन सब के बीच घटना को लेकर अन्य तकनीकी सबूत भी एकत्रित करने में पुलिस की टीम जुटी है.

बता दें कि गुरुवार की रात लगभग 10:30 बजे मैगी खाने के लिए पुलिस पदाधिकारी का पुत्र ऋतिक यादव अपने साथियों के साथ बंदरकुप्पी में स्थित मैगी पॉइंट गया था. यहीं पर सतीश यादव से कहासुनी हुई. जिसके बाद सतीश ने अपने साथियों को बुलाया और ऋतिक के साथ उसके दोस्तों की पिटाई कर दी. ऋतिक को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई.

गिरिडीह में एएसआई के बेटे की हत्या, 8 से 10 लोगों ने पीट-पीटकर ले ली जान, जेएमएम छात्र मोर्चा से जुड़ा था युवक

गिरिडीह, एजेंसी। जिले के प्रसिद्ध मैगी पॉइंट के पास एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना गुरुवार की रात लगभग 11 बजे की है. मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के राजेंद्र नगर (बभनटोली) निवासी ऋतिक यादव ऊर्फ बड्डी यादव (24 साल) के रूप में हुई है. घटना के बाद मुफस्सिल पुलिस सभी आरोपियों की खोज में जुटी है. मृतक के पिता झारखंड पुलिस के एसआई पद पर पदस्थापित हैं.

घटना को लेकर सदर अस्पताल में मृतक के साथी शुभम दास ने बताया कि रात लगभग 10.30 में वह, उसका दोस्त राजा गुप्ता और ऋतिक यादव कार पर सवार होकर गिरिडीह-डुमरी पथ पर अवस्थित बंदरकुप्पी गए थे. यहां मैगी पॉइंट है, जहां रातभर मैगी, कॉफी और चाय मिलता है. तभी पीरटांड थाना इलाके के नावाडीह निवासी सतीश यादव अपने 8-10 साथियों के साथ वहां पहुंचा और अचानक उनपर हमला कर दिया. पहले उन्होंने मुक्के से वार किया. मुक्के की पिटाई में कुछ नहीं हुआ तो फिर बांस की फराठी (बांस का टुकड़ा) से पिटाई शुरू कर दी. इतना पीटा कि ऋतिक की जान ले ली. उन्होंने बताया कि अचानक हमला किया गया, फिर ऋतिक को पीटते हुए उसकी जान ले ली.

बालू लोडिंग के विवाद में ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

निरसा, एजेंसी। निरसा थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार को लेकर विवाद में एक ट्रक चालक की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी गयी. गंभीर रूप से घायल चालक की गुरुवार दोपहर इलाज के दौरान कोलकाता में मौत हो गयी. घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात बराकर नदी के किनारे पोलकेरा में कई बड़े ट्रक व हाइवा में जेसीबी मशीन से बालू लोड कराया जा रहा था. वहां बालू स्टॉक भी किया जाता है. बताया जाता है कि इनमें अधिकांश वाहन

पश्चिम बंगाल के थे. इसी दौरान एक 16 चक्का ट्रक के चालक का लोडिंग और चालान के पैसे के लेनदेन को लेकर कथित बालू कारोबारियों से विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडे और रड से चालक की पिटाई कर दी. मारपीट में करीब 35 वर्षीय चालक के सिर में गंभीर चोट आयी.

घटना के बाद वहां मौजूद अन्य वाहन चालकों ने उसे धनबाद के एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर उसे आगे के इलाज के लिए अशर्फी अस्पताल और फिर कोलकाता ले जाया गया. जहां गुरुवार दोपहर उसकी मौत हो गयी. संबंधित ट्रक को उसी क्षेत्र के एक पंचायत भवन के समीप खड़ा रखा गया था. घटना के बाद वाहन मालिक भी निरसा पहुंचा. स्थानीय लोगों के अनुसार, बालू लोडिंग का काम कथित रूप से अवैध होने के कारण मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की गयी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि निरसा क्षेत्र में अवैध कोयला और बालू कारोबार से जुड़े लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है. पिछले दिनों राजा कोलियरी के महताडीह के समीप भी कोयला कारोबार से जुड़े विवाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आयी थी. वहीं चापापुर ओसीपी में कुछ दिन पूर्व सीआईएसएफ के जवानों को कथित तौर पर कई घंटे तक बंधक बनाये रखने और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किये थे.

रांची हिंसा मामला: पांच दोषियों को दो-दो साल की सजा

रांची, एजेंसी। 10 जून 2022 को रांची में हुए हिंसक जुलूस और उपद्रव से जुड़े डेली मार्केट थाना कांड संख्या 16/2022 में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-24, रांची की अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी रितविका सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाया.

दोषी ठहराए गए आरोपियों में मो. उस्मान उर्फ करण, मो. तवारू उर्फ तबारक कुरैशी, मो. सरफराज आलम, मो. साबिर अंसारी और मो. अफसर शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 147, 353/149, 504/149 और 120बी के तहत दोषी माना. वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर धारा 148 और 341/149 के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया.

अदालत के फैसले के अनुसार, 10 जून 2022 को करीब 8 से 10 हजार

लोगों के जुलूस के एकरा मस्जिद से फिरायालाल चौक की ओर बढ़ने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस के अनुसार, जुलूस के पास पूर्व अनुमति नहीं थी और पुलिस ने लाउडस्पीकर से उसे रोककर भीड़ को वापस लौटने के लिए कहा था. अभियोजन के मुताबिक, इसके बावजूद जुलूस आगे बढ़ा और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज तथा पथराव की स्थिति बनी. मामले में पुलिस की ओर से कुल 10 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया था. इनमें पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल थे, जबकि दो गवाहों को अदालत के रिकॉर्ड में होस्टाइल विटनेस बताया गया है. अभियोजन साक्ष्य 15 जुलाई 2026 को बंद हुआ और 10 अगस्त 2026 को आरोपियों के बयान दर्ज किए गए.

अदालत के रिकॉर्ड में गवाहों ने जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव और पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की बात कही. एक गवाह ने पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगने और कई पुलिसकर्मियों के पत्थर लगने से घायल होने की बात कही. वहीं डेली मार्केट थाना प्रभारी रहे गवाह ने अपने सिर में पत्थर लगने और अस्पताल में इलाज कराने की बात अदालत में बताई.

अदालत ने अपने निष्कर्ष में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा कि आरोपित बिना अनुमति निकाले गए जुलूस में शामिल थे और पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद जुलूस आगे बढ़ा. हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि अभियोजन यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया कि भीड़ के पास किस प्रकार के घातक हथियार थे. इसी आधार पर धारा 148 के आरोप में दोष सिद्ध नहीं हुआ.अदालत ने धारा 147 के तहत दो साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 353/149 के तहत दो साल और 3,000 रुपये, धारा 504/149 के तहत दो साल और 3,000 रुपये, जबकि धारा 120बी के तहत छह महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना लगाया है.

खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट रद्द

रांची, एजेंसी। राजधानी रांची में गुरुवार को खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश का असर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन पर पड़ा. बारिश और कम दृश्यता के कारण रात में कई उड़ानें निर्धारित समय से देरी से चलीं, जबकि इंडिगो की दिल्ली जाने वाली एक उड़ान को रद्द कर दिया गया.

इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 6274 को रात 8:35 बजे रांची से रवाना होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया. वहीं, पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 6272 भी करीब चार घंटे की देरी से चल रही है. रात 8:50 बजे निर्धारित इस उड़ान के 25 सितंबर की रात 12:40 बजे के आसपास रवाना होने की उम्मीद है. इसके अलावा कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 7235 भी निर्धारित समय रात 9:25 बजे के बजाय करीब 45 मिनट की देरी से रात 10:10 बजे रवाना हुई. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट आईएक्स 1053 भी देरी से चली और रात 9:39 बजे रांची से रवाना हुई.

रांची एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के कारण रांची और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इससे एयरपोर्ट पर दृश्यता प्रभावित हुई है और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

रिनपास में शुरू होगी 20 बेडेड इंडोर बाल एवं किशोर चिकित्सा इकाई

रांची, एजेंसी। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आज गुरुवार को नेपाल हाउस मंत्रालय में दो महत्वपूर्ण बैठक कर कई अहम निर्देश दिए. जिसमें रिनपास में 20 बेडेड इंडोर बाल एवं किशोर चिकित्सा इकाई स्थापित करने और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में यूजी-पीजी सीटें बढ़ाने के साथ-साथ फैकल्टी और स्टाफ पुनर्गठन का निर्देश शामिल है.

रिनपास को लेकर हुई बैठक में अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, रिनपास की निदेशक डॉ. जयति सिमलाई, सहायक निदेशक मिथिलेश चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने रिनपास में वर्तमान 100 बेडेड साईकेट्रिक रेजिडेंशियल शेल्टर होम की स्थिति और उपलब्ध क्षमता की जानकारी ली. उन्होंने संस्थान में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा व्यवस्थाओं का आकलन करते हुए आवश्यक सुधार एवं विस्तार की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए रिनपास में डीपीएन कोर्स को दोबारा शुरू करने की जरूरत है. उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके साथ साइकाइट्रिक नर्सिंग क्लासेस चलाने हेतु सारी व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया.

अपर मुख्य सचिव ने रिनपास में एमडी साईकेट्रिक का कोर्स भी दोबारा शुरू करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश निदेशक को दिया. साथ ही कहा कि इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएगी.

इस बैठक में रिनपास में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों कीसमीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पदों का एक बार पुनर्मूल्यांकन कर आवश्यकता के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग की

जाए,जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के पदों की आवश्यकता है, उसका आकलन कर प्रस्ताव तैयार किया जाए.

इस दौरान उन्होंने बाल एवं जेरिएट्रिक क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट की पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा और उपचार की सुविधाओं का विस्तार होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. साथ ही रिनपास की पुरानी प्रतिष्ठा और बेहतर कार्यप्रणाली को फिर से स्थापित करने की दिशा में भी काम किया जाए.

सचिव अजय कुमार सिंह ने दूसरी समीक्षा बैठक में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से एक सप्ताह में वहां की पूरी रिपोर्ट मांगी है. राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की तैयारी के तहत सीटों में वृद्धि के अनुरूप फैकल्टी, डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों को वर्तमान मानव संसाधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों की हुई इस समीक्षा बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, मेडिकल एजुकेशन निदेशक डॉ. पी. भट्टाचार्य सहित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य/अधीक्षक शामिल हुए.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए सिविल वर्क के साथ पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है. इसलिए प्रत्येक संस्थान में डॉक्टर, फैकल्टी, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की आवश्यकता का विस्तृत आकलन किया जाए.उन्होंने यूजी और पीजी सीट बढ़ाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने को कहा.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फैकल्टी की कमी होने पर आवश्यकता के अनुसार संविदा पर प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा सकती है. ऐसे में जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने और दूसरे राज्यों व शहरों से भी योग्य प्रोफेसरों को बुलाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया. इसका पूरे देश में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश उन्होंने दिया ताकि अन्य राज्यों से योग्य प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की सेवाएं ली जा सकें.

उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों में अगले तीन वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया, एसएनएमएमसीएच धनबाद की ओर से बताया गया कि वर्ष 2030 तक की योजना तैयार की गई है. जिसमें यूजी की 250 और पीजी की 200 सीट बढ़ाने का प्रस्तावित लक्ष्य शामिल है,जिसके आधार पर सभी शैक्षणिक और गैस शैक्षणिक पदों को रिस्ट्रक्चर करने का निर्देश दिया गया.

संक्षिप्त समाचार

26 सितंबर को रामपुरहाट में 1 घंटे का पावर ब्लॉक: जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु 30 मिनट रहेगी लेट

पटना, एजेंसी। रेलवे द्वारा रामपुरहाट स्टेशन क्षेत्र में जरूरी विकास और रखरखाव कार्यों को पूरा करने के लिए 26 सितंबर को पावर ब्लॉक लेने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान ओवरहेड तारों और पटरियों के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा. इस पावर ब्लॉक के कारण रेलवे ने बर्दवान और रामपुरहाट के बीच चलने वाली कुछ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव और नियंत्रण किया गया है.रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा डिवीजन के रामपुरहाट में आगामी 26 सितंबर 2026 को 60 मिनट (1 घंटे) का ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा. यह ब्लॉक दोपहर 11:30 बजे से शुरू होकर 12:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.ब्लॉक की अवधि के दौरान रामपुरहाट स्टेशन और आसपास के सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा ताकि विकास कार्यों को सुरक्षा मानकों के साथ पूरा किया जा सके.

बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर और पटना में बनेगी माता सीता महिला यूनिवर्सिटी

पटना, एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. जिसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में शिक्षा, पशुपालन और उद्योग से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी. वहीं पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को भी स्वीकृति दी गई. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर बिहार कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पदाधिकारी और कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने कहा कि दिनकर की साहित्यिक और राष्ट्रचेतना की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है. कैबिनेट ने पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है. विश्वविद्यालय के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि से जुड़े खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है. कैबिनेट ने पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत बैंक से लिए गए ऋण के ब्याज पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. इसका मतलब है कि लाभुकों को केवल मूलधन चुकाना होगा. योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट ने कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास से जुड़ी आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों और डेयरी सुविधाओं के विकास की योजना है. इन योजनाओं के लिए 126.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है. सरकार के मुताबिक, इससे नवादा के साथ नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को फायदा मिलेगा. इन जिलों के गन्ना किसानों के लिए चीनी मिल बाजार और प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में यह फैसला अहम है. कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा के साथ पशुपालन, डेयरी और चीनी उद्योग पर भी जोर दिया गया है. दिनकर विश्वविद्यालय और महिला विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संस्थागत व्यवस्था बनेगी. वहीं गो-धन योजना और डेयरी परियोजनाओं से पशुपालकों को वित्तीय सहायता और डेयरी ढांचे के विस्तार का रास्ता खुलेगा.

बिहार के रिटायर्ड सूबेदार की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचा मामला

सिवान, एजेंसी। बिहार के एक रिटायर्ड फौजी की जमीन पर भू-माफियाओं के द्वारा कब्जा का मामला देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंच गया। रिटायर्ड फौजी ने रक्षा मंत्री को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब रिटायर्ड सूबेदार शेख अशरफ अली अपने फौजी दोस्तों से मिलने के लिए हरियाणा गए। वहां जाकर वीडियो जारी कर सरकार से आग्रह किया कि, उनकी और उनकी जमीन की रक्षा की जाए। शेख अशरफ अली सिवान जिले के एमएच नगर के रहने वाले हैं। बताया कि सेना में रहते हुए उन्होंने साल 2001 में सिवान शहर के लछमीपुर में तीन कट्ठा जमीन खरीदी थी। उस समय जमीन की घेराबंदी कर गेट लगाकर छोड़ दिया था। अभी रिटायरमेंट के बाद सोचा कि उस जमीन पर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहूं, लेकिन भूमाफियाओं ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। 'भूमाफिया 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, तब जमीन पर घर बनाने देंगे। इस धमकी के बाद मैंने पुलिस से सहायता लेकर चारो तरफ दीवारी करायी। दिल्ली में दोस्तों से मिलने आया हूं, यहां आने के बाद पता चला कि भूमाफियाओं ने मेरी जमीन में घेराबंदी में लगे गेट को काटकर ले गए शेख अशरफ अली ने सिवान के शेख मोहल्ला निवासी मो। सलीम, मो। एहसान, मो। मुस्तफा, साजिद लंगड़ा और छोटे पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारी और हमारी जमीन की रक्षा की जाए। शेख अशरफ अली के फौजी साथी और रिटायर्ड सूबेदार बीसी चौहान ने बताया कि, इन्होंने बिहार के मंत्री, अधिकारी सभी के पास गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक आवेदन दिए हैं, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। बीसी चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस देश में कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है, जो इस रिटायर्ड फौजी की गुहार सुन सके।

जमुई के बाद समस्तीपुर, अब बांका, घटना होती रही, वीडियो बनते रहे,

बिहार में लड़कियां कितनी सुरक्षित?

जमुई, एजेंसी। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लड़कियों के साथ बदसलूकी से जुड़े चार वीडियो सामने आए हैं. मामला तीन जिलों का है- जमुई, समस्तीपुर और बांका. इनमें सबसे पहले जमुई का वीडियो सामने आया. इसके बाद समस्तीपुर में दो अलग-अलग मामले सामने आए और अब बांका के मंदार पर्वत का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंच गया. चारों मामलों की स्थिति एक जैसी नहीं है. कहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कहीं ख्नद्धक्र दर्ज कर पहचान की जा रही है. एक मामले में पुलिस अभी वीडियो की सच्चाई और पूरी घटना की जांच कर रही है.

शुरुआत जमुई से हुई. 19 सितंबर की शाम एक नाबालिग छात्रा और उसका दोस्त मड़वा पहाड़ी इलाके से लौट रहे थे. रास्ते में युवकों के एक ग्रुप ने दोनों को रोक लिया. इस दौरान लड़के को पीटा गया और लड़की के साथ घटिया हरकत किया गया. लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत किए जाने और उसे जबरन उठाने की कोशिश का भी वीडियो सामने आया.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ख्नद्धक्र दर्ज की और जांच के लिए एसआईटी बनाई. शुरुआत में तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया. बाद में मुख्य आरोपी नंदन यादव और हरेराम यादव की भी गिरफ्तारी हुई.

पुलिस के मुताबिक नंदन यादव ने गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. इस मामले में कुल पांच गिरफ्तारियां की गई है.

जमुई मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भी कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक 225 लोगों को चिन्हित किया गया है. इनमें पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले पोस्ट और घटना से जुड़े वीडियो या एआई से तैयार पोस्ट फैलाने वाले लोग शामिल हैं. पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में साइबर थाना कांड भी दर्ज किया गया है.

जिला प्रशासन ने मामले में स्पीडी ट्रायल की तैयारी भी शुरू की है. प्रशासन ने 15 से 20 दिनों में इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य बताया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बिहार के ष्ठत्रक्कसे कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

जमुई की घटना के बाद समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया. पुलिस के मुताबिक यह घटना करीब 15 सितंबर की है, जबकि वीडियो 23 सितंबर की रात सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस के सामने आया. पुलिस ने घटनास्थल की पहचान की और करीब छह घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार, राहुल कुमार, राम बाबू सहनी और अवधेश पासवान के रूप में हुई है. जिस मोबाइल से वीडियो आगे भेजे जाने की बात पुलिस ने कही, उसे भी जब्त किया गया है. पुलिस ने लोगों से पीड़िता की पहचान बताने वाला वीडियो या पोस्ट शेयर नहीं करने की अपील की है.

समस्तीपुर से ही एक और वीडियो सामने आया. इसमें एक युवक और युवती को लोगों की भीड़ से घिरा हुआ दिखाया गया है. यह मामला मुसरीघरारी थाना क्षेत्र की लाटबसेपुरा पंचायत से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में भीड़ द्वारा युवक-युवती के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट दिखाई देती है. पुलिस वीडियो की सच्चाई, घटना कब हुई और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच कर रही है.

समस्तीपुर के बाद अब बांका के प्रसिद्ध मंदार पर्वत से वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ युवक एक युवती के साथ बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस को 22 सितंबर को वीडियो की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर वीडियो में दिख रहे स्थान की पुष्टि की.

चार घटनाओं के वीडियो इतने कम समय में सामने आने से सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है. सवाल यह भी है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ घटना के बाद की कार्रवाई काफी है, या उन जगहों पर पहले से सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है जहां लड़कियां और परिवार बड़ी संख्या में आते-जाते हैं.

जमुई में मड़वा पहाड़ी, समस्तीपुर में बांध के आसपास का इलाका और बांका में मंदार पर्वत- तीनों मामलों ने अलग-अलग जगहों पर सुरक्षा को लेकर चिंता सामने रखी है. यह अब सिर्फ वायरल वीडियो का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी का सवाल बन गया है.

फर्जी आरपीएफ की 'वर्चुअल किडनैपिंग' का खूनी अंत, चलती ट्रेन से फेकने वाले कातिल तक ऐसे पहुंची बक्सर पुलिस

बक्सर, एजेंसी। बक्सर-डीडीयू रेलखंड पर सामने आई इस वारदात में पुलिस के अनुसार आरोपी ने आरपीएफ अधिकारी होने का झांसा देकर एक यात्री को अपने कब्जे में लिया। आरोप है कि इसके बाद यात्री के परिजनों से पहले 10 हजार और फिर 20 हजार रुपये की मांग की गई। कुछ देर बाद यात्री का मोबाइल बंद हो गया और करीब 24 घंटे के भीतर उसका शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच, जिसमें मोबाइल की गतिविधियों ने पुलिस को कथित आरोपी तक पहुंचाया। आरोपी को पटना लाया जा चुका है।

मृतक की पहचान वैशाली जिले के चांदसराय गांव निवासी मुकेश राय के पुत्र नितिन कुमार के रूप में हुई है। नितिन हैदराबाद में मजदूरी करता था और 20 सितंबर को हैदराबाद-दानापुर स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहा था। रात करीब 10 बजे उसने परिवार को फोन कर बताया था कि वह बक्सर पहुंचने वाला है। परिवार को क्या पता था कि यह उसके साथ आखिरी बातचीत में से एक होगी।पुलिस के अनुसार, नितिन ने बाद में परिजनों को फोन कर बताया कि उसे आरपीएफ ने पकड़ लिया है और छोड़ने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले परिवार से 10 हजार रुपये मांगे गए। कुछ समय बाद कथित तौर पर मांग बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई। इसके बाद नितिन का मोबाइल अचानक बंद हो गया।नितिन से संपर्क टूटने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई। मामला संदिग्ध लगने पर रेल पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की गतिविधियों और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो नितिन के साथ किसी अनहोनी की आशंका मजबूत होती गई।करीब 24 घंटे के भीतर आरा के जगजीवन हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक से नितिन का शव बरामद किया गया। इसके साथ ही जांच का स्वरूप बदल गया। पुलिस के सामने अब सिर्फ यात्री के लापता होने का मामला नहीं था, बल्कि अपहरण, फिरौती की मांग और मौत की परिस्थितियों की जांच भी सामने थी।

पटना में 27 सितंबर को होगा 14वां बिहार शिक्षक सम्मान समारोह, सीवान के 110 शिक्षाविद होंगे सम्मानित

सीवान, एजेंसी। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 27 सितंबर को राजधानी पटना स्थित रविंद्र भवन में 14वां बिहार शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह का विधिवत शुभारंभ सुबह 9:30 बजे से होगा, जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों के निजी विद्यालयों के निदेशक, प्राचार्य एवं शिक्षक भाग लेंगे. एसोसिएशन के सीवान सचिव शिवजी प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राज्यस्तरीय मंच पर सीवान जिले के 110 निदेशकों एवं शिक्षाविदों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा.

सचिव शिवजी प्रसाद ने बताया कि सीवान जिले में लगभग 1200 निजी विद्यालय संचालित हैं. इनमें से उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल तैयार करने और समाज निर्माण में अमूल्य भूमिका निभाने वाले 110 शिक्षाविदों को एक साथ राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाना जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि संगठन के अध्यक्ष प्रभात चंदा की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सैयद शमायल अहमद के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले कर्मठ शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. शिवजी प्रसाद ने बताया कि पूरे बिहार के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि इस भव्य समारोह का हिस्सा बनेंगे. जिले से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षाविदों का सम्मानित होना पहला ऐतिहासिक अवसर है.

पटना जू पर 9.88 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, इन निजी संपत्तियों पर भी निगम का शिकंजा, ार-घर पहुंच रही टीमें

पटना, एजेंसी। पटना नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए राजधानी में बड़े स्तर पर डोर-टू-डोर अभियान तेज कर दिया है. आमतौर पर हर वित्तीय वर्ष में सितंबर माह समाप्त होने के बाद टैक्स वसूली अभियान चलाया जाता था, लेकिन इस बार निगम ने पहले ही टीमें गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम की विशेष टीमें चिह्नित निजी और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंचकर टैक्स संबंधी विवरण की जांच कर रही हैं और मौके पर ही बकाया राशि का भुगतान प्राप्त कर रही हैं.

अभियान के तहत निगम का मुख्य फोकस निजी संपत्तियों के साथ-साथ सरकारी विभागों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने पर भी है. समीक्षा में सामने आया है कि संजय गांधी

जैविक उद्यान (पटना जू), बुडको, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय समेत कई प्रमुख सरकारी संस्थानों पर करोड़ों रुपये का टैक्स लंबे समय से लंबित है. निगम की टीमें संबंधित विभागों से संपर्क कर बकाया टैक्स के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही हैं.

नगर निगम की समीक्षा के अनुसार, सरकारी संस्थानों में संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना जू पर सबसे अधिक करीब 9.88 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. इसके अलावा सीजीएसटी कार्यालय से संबंधित संपत्तियों पर करीब 3.78 करोड़, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पर 3.77 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर 3.19 करोड़, बुडको पर 3.09 करोड़ और जिलाधिकारी कार्यालय पर करीब 2.01 करोड़ रुपये का टैक्स लंबित है.

डोर-टू-डोर जांच के दौरान निगम को प्रमुख गैर-सरकारी संपत्तियों पर भी बड़ी राशि बकाया मिली है. चिह्नित शीर्ष पांच निजी बकाएदारों पर ही कुल 1.94 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स लंबित है. इनमें चार संपत्तियां पाटलिपुत्र अंचल और एक संपत्ति नूतन राजधानी अंचल के अंतर्गत आती है.इनमें उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड पर अकेले 65.48 लाख रुपये की देनदारी है.

पितृपक्ष मेले में इस बार दिखेंगे सेल्फी प्वाइंट और फ्लोटिंग लोटस लाइट, विष्णुपद की रोशनी वाली आकृति भी बनेगी आकर्षण

गया जी, एजेंसी। पितृपक्ष मेला 2026 की तैयारियों में नगर निगम जुटा है. 2500 कर्मियों की तैनाती, प्रमुख घाटों का कायाकल्प, लेजर शो और सेल्फी प्वाइंट जैसे आकर्षण तीर्थयात्रियों का मन मोह लेंगे.

राजकीय पितृपक्ष मेला 2026 के सफल और सुचारू संचालन को लेकर नगर निगम प्रशासन पूरी तरह तैयार है. मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को नगर निगम की ओर से एक विशेष प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर और सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने विस्तार से जानकारी साझा की.

मेयर डॉ. वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के आपसी सहयोग से इस वर्ष राजकीय पितृपक्ष मेले में नगर निगम की ओर से हर स्तर पर अभूतपूर्व और बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. निगम की पूरी कोशिश है कि गयाजी आने वाले सभी पिंडदानी और तीर्थयात्री यहां की सुंदर व्यवस्था को देखकर अपने साथ एक सकारात्मक

संदेश लेकर वापस लौटें.

सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि विष्णुधाम गयाजी का धार्मिक महत्व केवल पितृपक्ष के दौरान ही नहीं, बल्कि सालभर रहता है. मेले को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी 7 प्रमुख घाटों, 38 वेदियों और 7 तालाबों की विशेष रूप से साफ-सफाई कर उनका रंग-रोगन किया गया है. मेला क्षेत्र की व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए निगम और विभिन्न एजेंसियों के कुल 2500 कर्मियों को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा, लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से शहर की नाली-गली और सड़कों की स्थिति को काफी बेहतर बनाया गया है. मेला क्षेत्र में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए 236 चापाकल, 25 पनशालाएं, 17 वाटर एटीएम और अन्य प्याऊ को पूरी तरह दुरुस्त कर चालू कर दिया गया है. फल्गु नदी के पानी को पूरी तरह स्वच्छ बनाए रखने के लिए विशेष मशीनों के साथ कर्मचारियों की तैनाती की गई है.

तीर्थयात्रियों को गयाजी के पौराणिक और धार्मिक इतिहास से जोड़ने के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं. देवघाट पर 'लेजर एंड लाइट शो' की शुरुआत की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को धार्मिक और आध्यात्मिक मनोरंजन का अनूठा अनुभव मिलेगा. इसके अलावा ब्रह्मसत सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन एंड लाइट साउंड शो की व्यवस्था भी की गई है. मेला क्षेत्र को 5 जोनों और 54 सेक्टरों में बांटकर सफाई व्यवस्था के लिए तीन पालियों (शिफ्ट) में कर्मचारियों की तैनाती की गई है. यात्रियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के आवासन स्थलों पर पर्यवेक्षकों के साथ तीन-तीन कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है. रोशनी के पुख्ता इंतजाम के लिए 184 हाइमास्ट लाइट, 87 मिनी हाइमास्ट, 4000 से अधिक स्ट्रीट लाइट और शहर के सभी बिजली पोलों पर तिरंगा लाइट लगाई गई है. शहर में आकर्षक सेल्फी प्वाइंट, लोगो लाइट, फ्लोटिंग लोटस लाइट, विष्णुपद की प्रकाशयुक्त आकृति और पेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, साथ ही सभी सफाई कर्मियों के लिए निगम के लोगो वाले एक जैसे ड्रेस का इंतजाम किया गया है.

बिहार में भीषण हादसा, 15 लोगों से भरी नाव डूबी

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा हो गया है. जिले के औराई थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बागमती नदी की दक्षिणी उपधारा में 15 लोगों से भरी नाव डूब गई. हादसे में नाव पर सवार 14 लोग किसी तरह नदी से बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए, जबकि 15 वर्षीय एक किशोरी लापता है. घटना महेशवारा पंचायत के देवरा धर्मपुर गांव के समीप करीब सुबह 9 बजे की बताई जा रही है.

लापता किशोरी की पहचान देवरा धर्मपुर गांव निवासी होरिल पासवान की 15 वर्षीय बेटी रानी कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोग बागमती बांध के अंदर से मवेशियों के लिए चारा लेकर लौट रहे थे. इसी दौरान दक्षिणी उपधारा में नाव असंतुलित होकर नदी में पलट गई.

नाव के नदी में डूबते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. नाव पर सवार 14 लोग किसी तरह तैरकर नदी से बाहर निकल आए. वहीं रानी कुमारी का कोई सुराग नहीं मिल सका. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और किशोरी की तलाश शुरू कर दी.

एडीएम (आपदा) शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि आज सुबह करीब 10 बजे अंचलाधिकारी के माध्यम से नाव डूबने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. एसडीआरएफ की टीम औराई प्रखंड कार्यालय पहुंच चुकी है और जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी.

रेस्क्यू में तीन घंटे से अधिक की देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटना की सूचना करीब 10 बजे प्राप्त हुई थी.

अशोक चौधरी बोले- 'जापान में भी होती है ऐसी घटना, रोकना संभव नहीं',

छात्रा से छेड़खानी पर बिहार के नेताओं ने क्या-क्या बयान दिया

पटना, एजेंसी। बिहार के जमुई और समस्तीपुर में छात्राओं से बदसलूकी और छेड़खानी के वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को एक विवादित बयान दिया है कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी होती हैं. ऐसी घटनाओं को रोकना किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए यह दावा करना संभव नहीं है कि उसके यहां कभी अपराध नहीं होगा.

अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देना चाहती. कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दोनों मामलों में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

मंत्री ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख रखती है.

वहीं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कोई अपराध करने के बाद अपना वीडियो क्यों बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा. उन्होंने इन घटनाओं के पीछे सरकार को बदनाम करने की साजिश होने की आशंका जतायी और कहा कि इस मामले में कुछ तो बात है.

जायसवाल ने कहा कि वीडियो सामने आने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जाने के तरीके की भी जांच होनी चाहिए. हालांकि, घटना और आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही होगा.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समस्तीपुर की घटना को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कानून-व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से

बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं.

चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने जमुई मामले में हुई पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए समस्तीपुर मामले में भी उसी तरह की कार्रवाई की मांग की.

समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने घटना को पीड़ादायक बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तेजी से कार्रवाई की है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, इसके लिए प्रशासन को तत्पर रहना चाहिए. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, समस्तीपुर मामले में पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की पहचान कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

समस्तीपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, वीडियो की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल की पहचान की गयी और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गयी. रिपोर्टों के मुताबिक, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

जमुई की घटना में भी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच जारी है. घटना से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किये जाने को लेकर भी पुलिस ने लोगों को सावधान किया है.

जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं के बाद बिहार में महिला सुरक्षा, पुलिस कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. सरकार की ओर से कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी का हवाला दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी और अन्य राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रशासन की जवाबदेही और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं.

संक्षिप्त समाचार

हरीश के नेतृत्व में बिहार में भाजपा को मजबूत करेंगी संगीता

गोरखपुर , एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर व्यापक बदलाव किया है जिसमें गोरखपुर-बस्ती मंडल के दो दिग्गज नेताओं को बिहार संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। हाल में ही राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हरीश द्विवेदी को नया प्रभारी बनाया है। उनके साथ, चौरी-चौरा की पूर्व विधायक एवं राज्यसभा सदस्य संगीता यादव को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बिहार भाजपा के प्रभारी बनाए गए हरीश द्विवेदी मूलरूप से बस्ती जिले के रहने वाले हैं। वह बस्ती से लोकसभा सांसद भी रहे। वह छात्र जीवन से भाजपा से जुड़े और संगठन में कई अहम पदों पर उन्होंने जिम्मेदारियां निभाईं। इससे पहले वह भाजपा के असम प्रभारी रह चुके हैं। अब उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ सह प्रभारी बनाई गईं संगीता यादव अभी राज्यसभा सांसद हैं। वह गोरखपुर जिले की चौरी-चौरी विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रहने के बाद हाल ही में नितिन नवीन की टीम में उन्हें जगह मिली। उन्हें इसी साल भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। अब सह प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया है।

जौनपुर में बैंक मैनेजर ने चलती कार में की आत्महत्या; पुलिस को मिला सुसाइड नोट

जौनपुर, एजेंसी। वाराणसी-लखनऊ नेशनल हाईवे-731 पर बैंक मैनेजर ने चलती कार में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. सुसाइड के बाद कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जा टकराई. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस पहुंची और घायल बैंक मैनेजर को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमितेश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान दुर्गेश श्रीवास्तव (35) पुत्र अवधेश श्रीवास्तव निवासी किरण एंक्लेव, कुर्सी रोड, टेढ़ी पुलिया, थाना गुडंबा, लखनऊ के तौर पर की गई है. वह फिलहाल जौनपुर के वन विहार एरिया में रहते थे. दुर्गेश श्रीवास्तव बदलापुर स्थित एक बैंक में रीजनल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे.बुधवार को वह अपनी कार क्क32 हृ 4239 से बदलापुर से जौनपुर की ओर जा रहे थे, तभी थाना बक्शा क्षेत्र के द्वारिका होटल के पास हाईवे पर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया. सूचना मिलते ही बक्शा थाने की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.कार अंदर से पूरी तरह लॉक थी. पुलिस ने कार का शीशा तोड़ा और अंदर खून से लथपथ पड़े बैंक मैनेजर को बाहर निकाला. उन्हें तत्काल इलाज के लिए सीएचसी नौपेड़वां ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौके से मिला सुसाइड नोटः पुलिस को कार की तलाशी के दौरान एक पिस्तौल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस ने फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की मदद से सुसाइड नोट व अन्य साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लिया है.सुसाइड नोट में दुर्गेश श्रीवास्तव ने लिखा कि वह अपना जीवन स्वयं समाप्त कर रहे हैं और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए. उन्होंने सभी से माफी भी मांगी है.अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमितेश सिंह ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं पर गहराई से जांच जारी है. आत्महत्या के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए पुलिस बैंक मैनेजर के पारिवारिक और व्यावसायिक पहलुओं की भी जांच कर रही है.

राजेंद्र प्रसाद लॉ यूनिवर्सिटी भर्ती विवादः तीन सदस्यीय समिति ने सीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट

प्रयागराज, एजेंसी। प्रयागराज स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 12 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में कथित धांधली और यूजीसी मानकों की अनदेखी के मामले में जांच पूरी हो चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय जांच समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री स्तर से होने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हैं. फाफामऊ में बीते तीन वर्षों से किराए के भवन में चल रहे इस नवस्थापित विधि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर विवाद तब गहराया, जब चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सीधी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची. शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए 3 सितंबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. देवराज की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था. इस समिति में पूर्व प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) एमपी अग्रवाल और न्याय विभाग के प्रमुख सचिव उदय प्रताप सिंह को शामिल किया गया. जांच समिति ने 16 और 17 सितंबर को लखनऊ स्थित सचिवालय में चयन समिति के सभी 12 सदस्यों को तलब कर मैराथन पूछताछ की. मामले में सबसे अहम पूछताछ 16 सितंबर को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. उषा टंडन से हुई, जिनसे समिति ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार तीन घंटे तक तीखे सवाल किए. सूत्रों के मुताबिक, यूजीसी गाइडलाइन की अनदेखी पर कुलपति ने जांच समिति के सामने बचाव करते हुए तर्क दिया- 'विश्वविद्यालय यूजीसी से कोई वित्तीय अनुदान (फंड) नहीं लेता है. संस्थान में मुख्यमंत्री चेयरमैन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चांसलर हैं, लिहाजा चयन प्रक्रिया में संस्थान के अपने प्रावधान प्रभावी हैं. ' हालांकि, जानकारों का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम अर्हता और पारदर्शी चयन के लिए यूजीसी नियमावली की बाध्यता को दरकिनार करना गले नहीं उतर रहा. दो दिनों की गहन पड़ताल और बयानों के आधार पर समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को अग्रसारित कर दी है. अब गेंद पूरी तरह शासन के पाले में है कि वह चयन प्रक्रिया को हरी झंडी देता है या फिर इन नियुक्तियों को निरस्त कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश जारी करता है.

खामोशी' को मिलेगी आवाज; 150 पुलिसकर्मियों को

'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग

कानपुर, एजेंसी। किसी मुसीबत में घिरे व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है, लेकिन जब आवाज ही साथ न दे और फरियाद सिर्फ इशारों में सिमट जाए, तो खाकी का संवेदनशील होना सबसे जरूरी हो जाता है. इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी और अनूठी पहल की है.

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर पुलिस ऑडिटोरियम में 150 से अधिक पुलिसकर्मियों को 'साइन लैंग्वेज' की विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिससे मूक-बधिर पीड़ितों और पुलिस के बीच भाषा अब न्याय की राह में रोड़ा न बन सके.

150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने सीखी 'इशारों की भाषा': इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर के अलावा चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और 'मिशन शक्ति' से जुड़ी महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया. मकसद सिर्फ कुछ औपचारिक इशारे सीखना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जब भी कोई बधिर या बोलने में असमर्थ व्यक्ति थाने पहुंचे, तो पुलिसकर्मी शुरुआती स्तर पर उसकी पूरी बात समझ सकें और उसकी सही मदद कर सकें.

'नमस्ते' से आगे... कानूनी प्रक्रियाओं को भी इशारों में समझाः ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को सिर्फ सामान्य हाल-चाल पूछना नहीं, बल्कि जटिल प्रक्रियाएं भी सिखाई गई. एक्सपर्ट्स ने सांकेतिक भाषा के बेसिक संकेत, वर्णमाला (अक्षर), रोजमर्रा के शब्द और अभिव्यक्तियां सिखाई.इसके साथ ही, कानूनी प्रक्रियाओं और शिकायत दर्ज कराने से जुड़ी बातों को सांकेतिक भाषा में कैसे समझा जाए, इसकी व्यावहारिक जानकारी दी गई. विशेषज्ञों और इंटरप्रेटर्स की मदद से पुलिसकर्मियों ने खुद भी इशारों को दोहराकर अभ्यास किया.

महिला और बाल अपराधों में साबित होगी मददगारः इस पहल का एक अहम पहलू महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है. मिशन शक्ति और चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का मुख्य कारण यही है कि ऐसे मामलों में पीड़ित अपनी बात झिझक या भाषा की वजह से छिपा न ले. सही और समय पर संवाद से पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाया जा सकेगा.

समावेशी और संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम': कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इस पहल को पुलिस की सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए कहा, समाज के हर वर्ग तक पुलिस की पहुंच होनी चाहिए. अगर भाषा किसी पीड़ित और पुलिस के बीच दूरी बनती है, तो उस दूरी को मिटाना बेहद जरूरी है.

एडीसीपी महिला अपराध सेल स्नेहा तिवारी ने बताया, अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के समन्वय से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. हमारे 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने बेसिक साइन लैंग्वेज सीखी है. हमें पूरा विश्वास है कि इससे भविष्य में दिव्यांगजनों की बेहतर मदद करने और संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता मिलेगी. दिव्यांगजनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा का संकल्पः जब एडीसीपी से सवाल पूछा गया कि अमूमन पुलिस का व्यवहार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील न होने की शिकायतें आती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क्ठ र्यशाला का मुख्य उद्देश्य ही पुलिसकर्मियों को 'सेंसिटाइज' करना था.

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके कानूनी अधिकार मिलें और वे बिना किसी झिझक अपनी भावनाएं और कष्ट पुलिस के सामने रख सकें, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और सांकेतिक भाषा सिखाने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया.

ग्रेटर नोएडा बस हादसा; मां चल नहीं सकती थी, बेटा साथ था... दोनों की मौत

महोबा, एजेंसी। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बीते 24 सितंबर को दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में आग लगने की घटना कई परिवारों को गहरे जख्म दे गई. दुर्घटना में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. इनमें महोबा जिला कोषाध्यक्ष नीरज गुप्ता की पत्नी सुनीता गुप्ता और बेटे शशांक गुप्ता की भी जान चली गई है. मां-बेटे दिल्ली से महोबा लौट रहे थे. दोनों की मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार में मातम पसरा है. परिजनों के अनुसार सुनीता गुप्ता पैरों की बीमारी के वजह से चलने-फिरने में असमर्थ थीं. वह दिल्ली में अपने बेटे शशांक के पास थीं और दोनों एक साथ बस से महोबा लौट रहे थे. हादसे के दौरान बस में आग तेजी से फैल गई. सुनीता खुद चलकर बाहर निकलने की स्थिति में नहीं थीं. शशांक भी मां को बचाने के चक्कर में फंस गया और आग की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई. शशांक दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था. परिवार के मुताबिक वह अपनी मां को लेकर महोबा लौट रहा था. आखिरी हो गया मां-बेटे का सफर : शशांक और उसकी मां बुधवार रात दिल्ली से महोबा के लिए रवाना हुए थे. परिवार को उम्मीद थी कि सुबह दोनों घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में बस अग्निकांड का शिकार हो गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग लगातार दोनों की तलाश में जुटे रहे. मां-बेटे की मौत की खबर चरखारी पहुंचते ही परिवार और परिचितों में चीख पुकार मच गई.

798 हेक्टेयर हुआ सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा, शून्य ईको जोन की अधिसूचना रद्द; जारी किया नया गजट

आगरा, एजेंसी। छह साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार का दायरा करीब 395 हेक्टेयर बढ़ाकर 798.1505 हेक्टेयर कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पक्षी विहार के ईको सेंसिटिव जोन को शून्य करने का अपना पुराना फैसला भी वापस ले लिया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 14.5025 हेक्टेयर सरकारी भूमि को आधिकारिक तौर पर पक्षी विहार का हिस्सा बना लिया गया है। पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने पूर्व में संरक्षित क्षेत्र का दायरा घटाने के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल के सख्त रुख के बाद शासन को संशोधित अधिसूचना जारी करनी पड़ी। यूपी सरकार ने 27 दिसंबर 2024 को जारी उस विवादित गजट को भी वापस ले लिया, जिसके तहत जमीन तो जोड़ी गई थी लेकिन ईको सेंसिटिव जोन को शून्य कर दिया गया था। डॉ. शरद गुप्ता की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। कमेटी ने स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है और ऐसा निर्णय केवल केंद्र सरकार ले सकती है। सीईसी की इसी रिपोर्ट के आधार पर शासन को कदम पीछे खींचने पड़े।

याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि यह आगरावासियों की जीत है। शहर को करीब 395 हेक्टेयर अतिरिक्त जंगल की सुरक्षा ढाल मिली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा सुनिश्चित करेगी। छह

संभल में गरजे लोनी विधायक; कहा-यह सिर्फ हिंदुओं का देश..., हलाला जैसी प्रथाएं हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी

संभल, एजेंसी। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है. बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के घर पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों को लपेटते हुए कई पूर्व नेताओं पर भी टिप्पणी की. इसके बाद राजेश सिंघल ने भगवान श्री कल्कि का चित्र भेंट कर विधायक नंदकिशोर गुर्जर का स्वागत किया.

मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चुनाव और वोटर लिस्ट को लेकर बयान दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दिल्ली के करीब 32 हजार मुस्लिम वोटर ऐसे थे, जो संभल और दिल्ली की दोनों वोटर लिस्ट में दर्ज थे. भाजपा सरकार में वोटर लिस्ट को शुद्ध करने और उसमें सुधार का काम चल रहा है. इसको लेकर कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग बेवजह बातें करते रहते हैं. चुनाव निष्पक्ष होते हैं. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग है. अगर कोई किसी मामले को लेकर कोर्ट जाता है तो कोर्ट उस पर निर्देश देता है.

लोनी विधायक ने कहा कि विपक्ष पर राहु की दशा चल रही है. 'रामद्रोही तनिक मम भावा ' और भोलेनाथ सर्वनाश करने वाले, भस्म करने वाले हैं. कहीं हनुमान जी का फोटो लगा रखा है और उसे आशीर्वाद के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि कार्यसेवकों पर गोली चलवाई गई. साधु-संतों का कत्ल करके उन्हें सरयू में डाल दिया गया. कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक रखी जाएगी. क्या हिंदू भगवान इन्हें आशीर्वाद देंगे. भगवान श्रीकृष्ण का भी फोटो लगाया जा रहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर होना चाहिए. हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, जो अपनी धर्मपत्नी के लिए नहीं बोल सकते. वे राम के लिए क्या बोलेंगे और बेटियों के लिए क्या बोलेंगे. उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में उनका सूपड़ा साफ कर देगी. विवादित बयान के सवाल पर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उन्होंने कभी विवादित बयान नहीं दिया. अगर कोई गाय काटेगा और बेटियों के साथ दुराचार करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रदेश में पहली बार होगा तेंदुओं का बधियाकरण

बरेली, एजेंसी। मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार तेंदुओं (गुलदारों) का बधियाकरण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत बिजनौर से की जाएगी। महाराष्ट्र (जुनार) के बाद ऐसा कदम उठाने वाला यूपी देश का दूसरा राज्य बनेगा। वन विभाग ने 601 करोड़ रुपये का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती बहराइच सहित अन्य कई जिलों में तेंदुए जंगल से निकलकर शहरी आबादी के आसपास खेतों में अपना घर बना चुके हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले बिजनौर में ही करीब 444 तेंदुए हैं। अगले पांच वर्षों में इनकी संख्या 201 फीसदी बढ़कर 1,336 हो जाएगी। वहीं, बधियाकरण के जरिये इसको 755 तक सीमित रखा जा सकता है।

पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 75 फीसदी (15त्न प्रतिवर्ष) तेंदुओं के बधियाकरण की योजना है। अभियान के तहत 310 किमी लंबी लोहे के तारों वाली चेन-लिंक फेंसिंग के साथ ही नदियों व रास्तों पर थर्मल नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी कमांड सेंटर से होगी।

मास्टर प्लान के अनुसार, वर्ष 1981 के बाद बिजनौर की जनसंख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वन विभाग में कुल 326 पदों में से आधे खाली पड़े हैं। इसके अलावा, आपातकालीन मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता भी शून्य है। ऐसे में तेंदुओं के बधियाकरण और इलाज के लिए 2.73 करोड़ रुपये से एक समर्पित वन्यजीव पशु चिकित्सा इकाई (अस्पताल) स्थापित की जाएगी। इसमें ऑपरेशन थिएटर, विशेष सर्जिकल उपकरण, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया मशीन और मल्टीपैरामीटर मॉनिटर्स से लैस प्री और पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड होगा

रुहेलखंड में 900 से ज्यादा तेंदुए हैं। बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों में इनकी संख्या 50 से 150 तक है। यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बिजनौर है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा, ढेलरी, कांठ में 100 से अधिक, सहारनपुर में 29 से 35 और बहराइच में 50 से अधिक तेंदुओं का सीधा दखल है। श्रावस्ती, बलरामपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र भी तेंदुओं का प्राकृतिक आवास है।

हॉटस्पॉट और अति संवेदनशील इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाकर पहचान की जाएगी। फिर उन्हें विशेष पिंजरों के जरिये पकड़ा जाएगा।

बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस, सीएम योगी ने जताया दुख

आगरा, एजेंसी। यूपी के आगरा के फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का गुरुवार रात निधन हो गया. विधायक छोटेलाल वर्मा बीते दो दिन से बुखार से पीड़ित थे. उन्हें गंभीर हालत में आगरा से नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार सुबह दिवंगत बीजेपी विधायक का पार्थिव देह आगरा के विभव नगर आवास पर पहुंची. जहां पर परिचित, रिश्तेदार, समर्थक, भाजपाई की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए. इसके बाद भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा की पार्थिव देह को लेकर परिजन, परिचित और रिश्तेदार पैतृक गांव नगला देवहंस पहुंचे. जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं सीएम योगी ने छोटेलाल वर्मा के निधन पर शोक जताया है.

दिवंगत बीजेपी विधायक के बेटे महेंद्र वर्मा ने बताया कि छोटेलाल वर्मा की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई थी. जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के दौरान हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने यहां से दिल्ली ले जा रहे थे. रास्ते में नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर उपचार के दौरान छोटे लाल वर्मा ने दम तोड़ दिया. नोएडा में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनको सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सके.

डीएम-कप्तान जैसे लेटरहेड पर बनाए आदेश, तस्करों-शातिरों से भी की वसूली

बरेली, एजेंसी। भमोरा थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अधिकारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से रुपये वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, आदेशों की छायाप्रति आदि बरामद हुए हैं। आरोपियों पर डीएम-एसएसपी समेत कई अधिकारियों के लेटरहेड जैसे भ्रामक पत्र बनाकर वसूली करने का आरोप है।

एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया किया कि मंगलवार रात भमोरा पुलिस ने सूचना के आधार पर ब्राह्मपुर गांव के पास एक बंद ईंट भट्ठे के पास घेराबंदी की। यहां से राजवीर राठौर और निकेत भारद्वाज को पकड़ा गया। राजवीर बारादरी जबकि निकेत भारद्वाज किला क्षेत्र का निवासी है। राजवीर ने बताया कि वह पप्पू मौर्य, शिवलाल मौर्य और शशांक वर्मा के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार कराता है। निकेत कचहरी में कंप्यूटर टाइपिंग करता है और फर्जी दस्तावेज बनाने में उसकी भूमिका रहती थी। इन दस्तावेज के जरिये वे अपराधियों व ऐसे लोगों को भ्रमित करते हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है या होने वाली है। इन लोगों से वसूली करके बैठ जाते थे।

बदायूं के अफीम तस्कर के परिवार से वसूली का खुला राज : गिरोह ने बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र के अफीम तस्कर परमानंद के परिवार से संपर्क किया था। परमानंद भमोरा थाने से तस्करी के मामले में बरेली जेल में बंद है। उस पर पिट एनडीपीएस एक्ट लगा है और साल भर जमानत की गुंजाइश नहीं है। गिरोह ने परमानंद के परिवार को बताया कि उनकी अधिकारियों के दफ्तरों में सीधी दखल है। वह उसके पिट के आदेश को निरस्त करवा सकते हैं। इससे संपत्ति जब्त होने का खतरा भी टल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इन लोगों ने पिट खत्म करने का भरोसा देने के लिए डीएम व एसएसपी के लेटरहेड को हुबहू एआई से तैयार करवा लिया। उस पर मुहर भी वैसी ही लगा ली और मनमाफिक दस्तखत करके परमानंद के परिवार को थमा दिया। इस तरह परिवार से कई बार में करीब साढ़े बारह लाख रुपये ले लिए।

यूपी में हेल्पलाइन नंबर '1912' उपभोक्ताओं के लिए कितना सही,

आंकड़ों से समझें पॉवर कॉरपोरेशन के कंज्यूमर का दर्द !

लखनऊ, एजेंसी। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने हेल्पलाइन 1912 स्थापित की, लेकिन वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिहाज़ से हेल्पलेस हो गई है. आलम ये है कि हेल्पलाइन पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर हो ही नहीं पा रहा है. समय गुजरने के बाद शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है. उपभोक्ता परिषद ने वर्टिकल व्यवस्था को समाप्त कर अधिक सरल, सीधे और ज़वाबदेह शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की मांग की है. इनमें 63,35,239 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में हो गया. वहीं 32,22,108 शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के बाद हुआ.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 1912 की शिकायत को समाधान तक पहुंचाने के बजाय अगर वह कई स्तरों की वर्टिकल व्यवस्था में घूमती रहे, तो जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है. उपभोक्ता को समय पर राहत नहीं मिलती.

यही कारण है कि शिकायत निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को सरल और सीधे ज़वाबदेही वाले मॉडल में बदलने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जिम्मेदारी कई स्तरों पर चली जाती है. इससे किस अधिकारी की ज़वाबदेही है, किस समय तक समाधान होना है और देरी के लिए किसे उत्तरदायी माना जाए, यह स्पष्ट रूप से तय करना कठिन हो जाता है. अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि वर्टिकल व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय इसे खत्म करने या पूरी तरह पुनर्गठित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए. 1912 को ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिसमें शिकायत सीधे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचे. समय सीमा स्वतः निर्धारित हो और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से ट्रैक हो. समय सीमा पार होते ही शिकायत स्वतः उच्च अधिकारी के स्तर पर एस्केलेट हो और देरी की जवाबदेही तय हो. इससे शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. उपभोक्ता को वास्तविक राहत मिलेगी. अवधेश वर्मा ने कहा कि 1912 को सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि उपभोक्ता को समयबद्ध न्याय और राहत देने वाली जवाबदेह व्यवस्था बनाना होगा. अगर मौजूदा वर्टिकल मॉडल इसके रास्ते में बाधा है, तो उसे खत्म कर नई व्यवस्था लागू करने पर सरकार और बिजली कंपनियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

जेन जी वोटर पर सियासत तेज: जयराम रमेश बोले- युवाओं से डरते हैं पीएम

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस फैसले का जिक्र किया, जिसके तहत 1988 में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एक प्रधानमंत्री ने युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, जबकि दूसरा जेन जी से यह अधिकार 'हथियाने' की कोशिश कर रहा है।

जयराम रमेश ने कहा, 'यह दो प्रधानमंत्रियों की कहानी है। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी सरकार ने संसद के नियमित शीतकालीन सत्र में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। उन्होंने इसे युवाओं को सशक्त बनाने वाला कदम बताया। ' कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 2024 से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को रोक दिया गया है, जिससे जेन जी के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'एक प्रधानमंत्री ने जेन जी को वोट का

अधिकार दिया, जबकि दूसरा इसे छीनने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने पर तुला हुआ है। ' कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जेन जी को मतदाता सूची से बाहर रखने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग भी की थी। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उसके अनुसार 'साजिश' के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं कि जेन जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज न हों। उन्होंने दावा किया कि युवाओं में सरकार के प्रति असंतोष को देखते हुए चुनाव आयोग के प्रमुख के जरिए उन्हें मतदाता सूची से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। रमेश ने कहा था कि हर साल मतदाता सूची में संशोधन के लिए होने वाला एसएसआर रोक दिया गया है। उनके मुताबिक, यही वह प्रक्रिया है जिसके जरिए खासकर 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में ईएलसी कॉन्फ्रेंस स्थगित होने पर चुनाव आयोग ने दी सफाई, कहा-तारीखों में बदलाव सामान्य प्रक्रिया

नई दिल्ली , एजेंसी। उत्तर प्रदेश में ईएलसी कॉन्फ्रेंस स्थगित होने को लेकर उठ रहे सवालों पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव एक सामान्य और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कई कारणों से जरूरी हो जाती है। ईसीआई ने बताया कि वेन्यू की उपलब्धता, उच्च अधिकारियों के कार्यक्रम और प्राकृतिक कारणों जैसे कई कारणों से तारीखों में बदलाव किया जाता है। आयोग ने कहा कि इससे पहले भी कई बार ईएलसी कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया गया है या तारीखें बदली गई हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में। आयोग ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की इन दो कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने का फैसला 21 सितंबर को ही लिया गया था। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मेरठ दौरा 25 सितंबर को प्रस्तावित था। वहीं 28 सितंबर को वाराणसी में कार्यक्रम होना था। इन कार्यक्रमों में युवाओं से संवाद के साथ-साथ चुनावी साक्षरता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली ईएलसी कॉन्फ्रेंस यानी चुनावी साक्षरता क्लब सम्मेलन भारत निर्वाचन आयोग की एक विशेष पहल है। इसका मकसद युवा पीढ़ी और छात्रों को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें जागरूक करना है। चुनाव आयोग युवा नागरिकों में लोकतांत्रिक जागरूकता और चुनावी शिक्षा को मजबूत करने के लिए चुनावी साक्षरता क्लब सम्मेलन (ईएलसी 2.0) और ईसीआईनेट ऐप पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस विभाग सख्त, कई जरूरी निर्देश जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी में हाल ही में हुए आस्था पार्क गैंग रेप मामले के बाद एक बार महिला सुरक्षा का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है. महिलाओं से संबंधित बढ़ते अपराधों को देखते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त ने महिला सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है. इसके मद्देनजर, महिला पुलिसकर्मियों को सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के अलग- अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहे है. महिला सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक स्थानों जैसे, पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन पुलिस की तैनाती देखी जा रही है. कई इलाकों में पुलिस रात्री गश्त लगाती नजर आयी. आयुक्त ने सुझाव दिया है कि मुख्यालय में तमाम अधिकारियों के कार्यालयों में ड्यूटी करने वाली महिला कर्मियों का इस्तेमाल फील्ड ड्यूटी में किया जाए. जिसका असर भी दिखा और महिला पुलिसकर्मी तैनात नजर आयीं. बता दें कि महिलाओं से संबंधित अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने गंभीर चिंता जाहिर की थी. वहीं घटनास्थल का दौरा करने के दौरान आयुक्त ने पाया कि घटना स्थल के आसपास अंधेरा था, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे. इस तरह की खामियां के बाद आयुक्त ने बुधवार को कई दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें डार्क स्पॉट, खराब पड़े स्ट्रीट लाइटें और पार्कों के आसपास बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे की पहचान करने, पार्कों की टूटी दीवारों, गेटों के बारे में सिविक एजेंसियों को सूचित करने, बीट स्टाफ और सुरक्षा गार्डों की पार्कों में तैनाती जेबकतरों व अपराधियों के पार्कों में प्रवेश पर पाबंदी और पार्कों में फिर से साइकिल गश्त शुरू करने के निर्देश दिए.

दिल्ली-एनसीआर में करवट लेगा मौसम, 3 दिन बारिश का अलर्ट; गर्मी-उमस से मिलेगी राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। मानसून की विदाई के बाद भी दिल्ली के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। शनिवार से अगले तीन दिन तक राजधानी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ तापमान में भी कुछ गिरावट आएगी। हालांकि शुक्रवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर बादलों की आवाजाही के साथ धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी जारी रहने की संभावना है। शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 84 दर्ज किया गया। इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों में भी हवा संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में रही। हालांकि मौसम शुष्क होने के साथ हवा की गुणवत्ता में गिरावट शुरू हो गई है।

पुराने ढर्रे पर सुनाया गया फैसला, बृजभूषण के बरी होने पर महिला पहलवानों ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा के पूर्व सांसद और रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली की कोर्ट में अपील की है। अदालत के एक महीने पुराने आदेश को चुनौती देते हुए महिला पहलवानों ने दलील दी है कि यह फैसला 'पुराने और दकियानूसी' है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच पर आधारित है, जो पीड़िताओं से एक निशितत तरह के व्यवहार की ही अपेक्षा करता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में बेहद कड़ी टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और गढ़े हुए प्रतीत होते हैं और प्रथम दृष्टया पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश का हिस्सा लगता है। अदालत ने तीन अगस्त को बृजभूषण सिंह और [illegible] के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को मामले में बरी कर दिया था। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने कहा कि अभियोजन के मामले की अहम कड़ी रहीं दो महिला पहलवान अदालत में अपने आरोपों से मुकर गईं।

रेल यात्रियों ध्यान दें, गाजियाबाद में साढ़े 7 घंटे का मेगा ब्लॉक; बदले गए 8 प्रमुख ट्रेनों के रूट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली मंडल के गाजियाबाद यार्ड में संरक्षा कार्य के चलते चार दिसंबर को साढ़े सात घंटे का ट्रैफिक ब्लाक लिया जाएगा। इसके कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। रेलवे ने आठ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। बदले मार्ग से चलने के कारण कई ट्रेनों के निर्धारित स्टॉपेज भी छूटेंगे।

इंदौर-जंक्शन-ऊना हिमाचल एक्सप्रेस (19307): चार दिसंबर को यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-तिलक ब्रिज-दिल्ली शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी के रास्ते चलेगी। इसका मेरठ सिटी स्टॉपेज छूटेगा।

कोटा-देहरादून नंदा देवी एक्सप्रेस (12401): यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-तिलक ब्रिज-दिल्ली शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी-रुड़की के रास्ते चलेगी। निर्धारित मार्ग के गाजियाबाद-मेरठ सिटी-देवबंद-बानहेड़ा खास के बजाय यह मार्ग अपनाया जाएगा। इसके गाजियाबाद, मेरठ सिटी और मुजफ्फरनगर स्टॉपेज छूटेंगे।

बांद्रा टर्मिनल-हरिद्वार एक्सप्रेस (19019): चार दिसंबर को यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन जंक्शन-तिलक ब्रिज-दिल्ली शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी के रास्ते चलेगी। इसके गाजियाबाद, मेरठ सिटी और मुजफ्फरनगर स्टॉपेज छूटेंगे।

साबरमती-योग नगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस (19031): यह ट्रेन पुरानी दिल्ली-दिल्ली शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी के रास्ते चलेगी। इसके गाजियाबाद, नया गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, सकोती टांडा, मुजफ्फरनगर और देवबंद स्टॉपेज छूटेंगे।

अमृतसर-बांद्रा टर्मिनल गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस (12904): यह ट्रेन टपरी-शामली-लोनी-दिल्ली शाहदरा-तिलक ब्रिज-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते चलेगी। इसके मुजफ्फरनगर, सकोती टांडा, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टॉपेज छूटेंगे।

देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस (12402): चार दिसंबर को यह ट्रेन रुड़की-टपरी-शामली-लोनी-दिल्ली शाहदरा-तिलक ब्रिज-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते चलेगी। इसके मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी और गाजियाबाद स्टॉपेज छूटेंगे।

अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (18238): यह ट्रेन टपरी-शामली-लोनी-दिल्ली शाहदरा-तिलक ब्रिज-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते चलेगी। इसके देवबंद, मुजफ्फरनगर, खतौली, दौराला, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मोदीनगर, गुलधर, गाजियाबाद और साहिबाबाद स्टॉपेज छूटेंगे।

रेस कोई और दौड़ा, हाइट किसी और की नापी, दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा

नई दिल्ली , एजेंसी। दिल्ली पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षा ([illegible]) के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. वजीरबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी ([illegible]) में चल रही चयन प्रक्रिया में एक ऐसा मामला पकड़ा गया, जहां असली अभ्यर्थी की जगह उसका सॉल्वर मैदान में दौड़ लगाकर चला गया और खुद अभ्यर्थी अपनी पीठ पर चेस्ट नंबर चिपकाकर सिर्फ माप (मेजरमेंट) कराने पहुंच गया. सतर्क साथी अभ्यर्थियों की सजगता और पुलिस की मुस्तैदी से यह फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अकादमी वजीरबाद में दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं. इसी दौरान 1600 मीटर की लंबी दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद के कड़े शारीरिक चरणों को पार करने के बाद उम्मीदवारों की छाती और ऊंचाई की माप तथा बायोमेट्रिक औपचारिकताएं पूरी की जानी थीं. इसी प्रक्रिया के दौरान 19 वर्षीय एक अभ्यर्थी, जिसकी पहचान अक्षत (पुत्र, निवासी- वीपीओ सिलाना, जिला सोनीपत, हरियाणा) के रूप में हुई है, को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और वहां खड़े

अन्य उम्मीदवारों का ध्यान इस बात पर गया कि इतनी भारी-भरकम शारीरिक गतिविधियों और पसीने से तरबतर कर देने वाले दौर के बावजूद अक्षत के शरीर पर न तो एक बूंद पसीना था और न ही मैदान की कोई धूल-मिट्टी.अन्य उम्मीदवारों ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और अधिकारियों को सूचित किया कि यह वही लड़का नहीं है जिसने मैदान पर दौड़ और कूद जैसी शारीरिक परीक्षाएं वास्तव में दी थीं. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान अक्षत ने स्वीकार किया कि उसने खुद दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था. उसके भाई ने उसकी जगह परीक्षा पास कराने के लिए एक अन्य सॉल्वर का इंतजाम किया था. वह सॉल्वर एक टेंपर्ड फर्जी एडमिट कार्ड के जरिए शातिर तरीके से अकादमी के अंदर घुस गया था. उस फर्जी अभ्यर्थी ने अक्षत की जगह मैदान पर सारी कठिन शारीरिक गतिविधियां पूरी कीं. इसके बाद, जब दौड़ और कूद का चरण समाप्त हो गया, तो वह सॉल्वर चुपचाप बाहर निकल गया और जाते-जाते अपना चेस्ट नंबर असली अभ्यर्थी अक्षत को सौंप गया, ताकि वह बायोमेट्रिक और माप परीक्षण के चरण में आसानी से शामिल हो सके.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी अक्षत को तुरंत सोनिया विहार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में धोखाधड़ी, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और साजिश रचने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली.

नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर खोले पत्ते: रिश्तों को बताया बेहतरीन, जयशंकर से मुलाकात का भी किया जिक्र

वॉशिंगटन , एजेंसी। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आता रहा है, लेकिन अभी नेपाल और भारत के बीच रिश्ते अच्छे दौर में हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडो भारत के साथ संबंधों में मतभेदों के बजाय अवसरों पर ध्यान देते हुए व्यावहारिक तरीका अपना रहा है।

शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध बहुत मजबूत और कई स्तरों वाले हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल के कुल व्यापार का करीब दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ होता है। दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी काफी मजबूत हैं। खनाल ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर कभी-कभी रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन मौजूदा समय में दोनों देशों के संबंधों को वह बेहतरीन मानते हैं। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल की नई सरकार के बीच संबंधों से जुड़े सवाल के जवाब में कही। खनाल ने बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच भारत-नेपाल संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें विकास साझेदारी और ऊर्जा सहयोग की प्रगति पर चर्चा हुई। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के

साथ संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। यह बातचीत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर हुई। भारत और चीन के बीच संतुलन को लेकर पूछे गए सवाल पर खनाल ने कहा कि नेपाल अब रिश्तों को केवल वैचारिक नजरिए से देखने के बजाय व्यावहारिक सहयोग पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा जैसे विवादित मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन नेपाल का मौजूदा तरीका यह देखने का है कि सहयोग के कौन-कौन से अवसर मौजूद हैं। भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को उन्होंने इसी व्यावहारिक नीति का उदाहरण बताया। खनाल ने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था आयात पर काफी निर्भर है, इसलिए ऊर्जा और व्यापार में सहयोग उसके लिए महत्वपूर्ण है। खनाल ने कहा कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसके लिए बड़ी आर्थिक संभावना बन सकती है। उन्होंने भारत के साथ 1,700 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा का जिक्र किया। यह सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से जुड़ती है। उन्होंने बताया कि नेपाल के पास आर्थिक रूप से उपयोगी करीब 43 गीगावाट जलविद्युत क्षमता है और देश 2035 तक 28,000 मेगावाट तक पहुंचने की दिशा में काम करना चाहता है। इससे भारत और आगे बांग्लादेश को स्वच्छ बिजली निर्यात करने की संभावना है। खनाल ने कहा कि नेपाल खुद को केवल भारत और चीन के बीच स्थित छोटे देश के रूप में नहीं देखता। उनका कहना है कि दोनों बड़े पड़ोसियों का आकार भौगोलिक सच्चाई है, लेकिन यह नेपाल की महत्वाकांक्षाओं की सीमा नहीं बनना चाहिए। चीन के साथ भी नेपाल का रुख व्यावहारिक और व्यापार आधारित रखने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नेपाल उत्तर और दक्षिण के रास्तों को एक-दूसरे का विकल्प नहीं मानता, बल्कि दोनों दिशाओं को जोड़कर देश को लैंडलॉक्ड यानी भू-आबद्ध अर्थव्यवस्था से लैंड-लिंक्ड यानी जमीन के रास्ते से जुड़े आर्थिक केंद्र में बदलना चाहता है।

रूस सिर्फ युद्धविराम को नहीं बल्कि वैश्विक शांति को बाधित करने के लिए वीटो कर रहा: यूक्रेन विदेश मंत्री

कीव, एजेंसी। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्य देश युद्ध समाप्त करने के पक्ष में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस रुख का विरोध करने वाला एकमात्र देश खुद रूस है। विदेश मंत्री के मुताबिक, रूस अपनी वीटो पावर (निषेधाधिकार) का इस्तेमाल सिर्फ युद्धविराम रोकने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शांति को बाधित करने के लिए कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह संघर्ष केवल यूक्रेन या यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। यूक्रेन पूर्ण और बिना किसी शर्त के युद्धविराम के लिए पूरी तरह तैयार है। सिबिहा ने सोशल मीडि?या प्?लेटफॉर्म 'एक ?स' पोस्?ट में कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इनमें से 14 सदस्य किसी न किसी रूप में तुरंत युद्धविराम का समर्थन करते हैं। इनमें चार स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। सिर्फ एक देश लड़ाई खत्म होने की राह में रुकावट डाल रहा है और वह खुद हमलावर देश है।'' सिबिहा ने कहा कि रूस सिर्फ युद्धविराम को वीटो नहीं कर रहा, बल्कि शांति को वीटो कर रहा है। पुतिन इस युद्ध को बहुत पहले खत्म कर सकते थे, लेकिन वह हर दिन तनाव और लड़ाई को और बढ़ाने का रास्ता चुन रहे हैं। उन्?होंने कहा कि यह युद्ध रुकना चाहिए। यूक्रेन इसे अभी खत्म करना चाहता है। हम पूर्ण और बिना किसी शर्त के युद्धविराम के लिए तैयार हैं। हम ऊर्जा और खाद्य से जुड़े मामलों में भी युद्धविराम के लिए तैयार हैं।

यूएन में बालेंद्र शाह का पहला भाषण: आपदा प्रबंधन पर दिया जोर

न्यूयॉर्क , एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में एक साझा तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की अपील की। बालेंद्र शाह ने कहा कि इस तंत्र के जरिए तीनों देश उपग्रह से मिले आंकड़े और विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं। साथ ही खतरनाक ग्लेशियल झीलों की निगरानी और संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई आपदा आए तो सीमाओं के पार राहत और सहायता के लिए समन्वय किया

जाना चाहिए। नेपाल के पीएम शाह ने कहा, 'हम नेपाल, भारत और चीन के नेतृत्व में हिमालयी जलवायु के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस तंत्र के जरिए उपग्रह डेटा और विशेषज्ञता साझा करें। खतरनाक ग्लेशियल झीलों की निगरानी करें। संयुक्त प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करें। जब आपदा आए तो सीमाओं के पार सहायता का समन्वय करें। हिमालय खंडित सूचनाओं की सीमा के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रयोगशाला बने। ' विभिन्न देशों और संगठनों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, 'मैं बाढ़ के बाद हमारी सहायता के लिए आगे आने वाले सभी लोगों के प्रति नेपाल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे तत्काल पड़ोसी भारत और चीन ने तेजी से और उदार सहायता प्रदान की। अन्य मित्र देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, मानवीय सहायता एजेंसियों, परोपकारी संगठनों और दुनिया भर के लोगों ने नेपाल का साथ दिया। उन सभी से मैं नेपाल की कृतज्ञ जनता की ओर से धन्यवाद कहता हूं। ' उन्होंने कहा, 'भोटेकोशी-त्रिशूली आपदा केवल एक स्थानीय त्रासदी नहीं थी, यह दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। मैं आज आपसे पूछता हूं: क्या हमने वास्तव में उस चेतावनी को सुना है? नेपाल के लिए जलवायु आपदा केवल मानवीय संकट नहीं, बल्कि विकास के लिए भी आपात स्थिति है।' शाह ने जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार और इससे निपटने की अधिक क्षमता रखने वाले देशों से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की अपील की।

नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ के एक महीने बाद भी 50 से ज्यादा यूक्रेनी लापता, परिवारों को जवाब का इंतजार

काठमांडू, एजेंसी। ओलेना कलिनिचेंको चीन से खरीदी गई गुलदाउदी की चाय अपने साथी के साथ साझा करने का इंतजार कर रही थीं। उनके साथी ओलेस विसिच ने कहा, 'उन्होंने कहा था, जब मैं घर लौटूंगी तो हम चीनी फूलों से बनी चाय साथ में पिएंगे।' अब वह एक महीने से ओलेना की खबर का इंतजार कर रहे हैं। ओलेना और हजारों अन्य लोग नेपाल-चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के दौरान लापता हो गए थे। ओलेना की आखिरी ज्ञात लोकेशन स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर एक सीमा चौकी से चीन से बाहर निकलते समय दर्ज हुई थी। इसके 15 मिनट बाद बाढ़ आ गई थी। 36 वर्षीय कलिनिचेंको उन 56 लोगों के समूह का हिस्सा थीं, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी नागरिक थे। यह समूह आध्यात्मिक प्रवास के लिए तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत गया था। इन परिवारों की स्थिति बताती है कि आपदा में लापता लोगों को बचाने, उनके शव बरामद करने और उनकी पहचान करने की प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। लापता लोगों की संख्या को देखते हुए इस प्रक्रिया में कई महीने लगने की संभावना है। ये लोग घर लौटते समय चीन से नेपाल की ओर जाते हुए लापता हुए। कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें अधिकारियों से कोई जानकारी नहीं मिली है। चीनी सरकार ने कम से कम दो परिवारों को बताया है कि उनके रिश्तेदार बाढ़ आने से पहले ही चीन की सीमा से बाहर निकल गए थे। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि वे नेपाल पहुंचे थे या नहीं। नेपाल का आव्रजन परिसर और उससे जुड़े रिकॉर्ड बाढ़ में नष्ट हो गए हैं, जिससे लापता लोगों की आवाजाही की पुष्टि करना और भी मुश्किल हो गया है।

संपादकीय | एसआईआर की सफाई में फंसते मतदाता!

चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ मतदाता सूची है। जब वह शुद्ध हो, तब लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन जब शुद्धिकरण का अर्थ ही लाखों-करोड़ों वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर कर देना बन जाए, तब चुनाव आयोग जैसी संस्था की विश्वसनीयता भी संकट में पड़ जाती है। चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) का यही विरोधाभास आज देश के कई राज्यों में साफ दिख रहा है।

देखा जाए तो आयोग का आधिकारिक लक्ष्य सही है, कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं, कोई अपात्र शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी एस.आई.आर. की वैधता को बरकरार रखा। लेकिन सवाल प्रक्रिया के सिद्धांत का नहीं, उसके क्रियान्वयन का है। घर-घर प्रगणन, 2002 की पुरानी सूची से मैपिंग, 'तार्किक विसंगति' जैसे अस्पष्ट श्रेणीबद्ध आधार और नोटिसों की बाढ़ ने आम मतदाता को अपराधी जैसा महसूस कराया है। इस प्रक्रिया के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार में मतदाता सूची लगभग 7.89 करोड़ से घटकर अंतिम रूप में करीब 7.42 करोड़ रह गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात समेत 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त सूची में भी करोड़ों नाम घटे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में कटौती बताई गई, पश्चिम बंगाल में भी 10 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज हुई। वहीं महाराष्ट्र में 2 करोड़ से अधिक नाम बाहर दिखे, कर्नाटक में 1 करोड़ से ऊपर, दिल्ली में करीब 47.56 लाख। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि पूरे देश में मसौदा स्तर पर लगभग 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। ये आंकड़े अंतिम स्थायी कटौती नहीं हैं, लेकिन पैमाना इतना बड़ा है कि 'शुद्धिकरण' शब्द ही संदेह

पैदा करता है।

दिल्ली का उदाहरण सबसे ताजा और सबसे चिंताजनक है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजधानी की सूची करीब 1.56 करोड़ थी। एस.आई.आर. शुरू होने से पहले ही यह घटकर लगभग 1.45 करोड़ रह गई। फिर प्रगणन में केवल 67 प्रतिशत फॉर्म जमा हुए और मतदाता सूची 97.53 लाख पर सिमट गई। यानी एक-तिहाई से अधिक नाम सूची से गायब। इसके बाद भी मतदाता सूची में शामिल करीब 33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। इनमें लगभग 13.79 लाख इसलिए, कि उनका नाम 2002 की गहन पुनरीक्षण सूची से मैप नहीं हो सका और 19.33 लाख 'तार्किक विसंगति' के नाम पर। वहीं दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बार-बार कहा है कि नोटिस का मतलब कटौती नहीं है, सुनवाई के बिना कोई नाम नहीं कटेगा। फिर भी लाखों परिवारों में अफरा-तफरी है। पश्चिम बंगाल का अनुभव और भी सबक देता है। वहां लाखों नाम 'संदिग्ध' श्रेणी में डाले गए। अपील न्यायाधिकरणों में निपटाए गए मामलों में बहाली की दर बहुत ऊंची रही। अगर सुनवाई के बाद इतने बड़े हिस्से को पात्र माना जा रहा है, तो पहले चरण में उन्हें अपात्र मानने की प्रक्रिया में गड़बड़ी स्पष्ट है। बिहार और बंगाल से दिल्ली आए प्रवासी मतदाता एक और जाल में फंस गए हैं-एक राज्य की सूची से नाम कटा, दूसरे में मैपिंग नहीं हुई, तीसरे में 'पहले से नामांकित' का ठप्पा लग गया। नतीजा, नागरिक तीनों जगहों पर वोट देने का हक खो बैठा। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार इस प्रक्रिया पर लिखित आपत्ति दर्ज की। जिसमें नई पंजीकरण प्रक्रिया, नाम जोडने-काटने, फॉर्म-6 में बदलाव, बंगाल में बहाली के आदेशों के खिलाफ अपील जैसे मुद्दों पर ध्यान आर्ज़षित किया गया। अखबार का दावा है कि कुछ नोट्स में फैसलों को उनकी जानकारी के बिना लिया गया बताया गया। इस पर आयोग का जवाब है कि मतभेद सामान्य विचार-विमर्श का हिस्सा हैं और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए।

बाबा नीब करौरी : मानव कल्याण ही था बाबा के जीवन का हेतु

दिवेश अनिलकुमार शर्मा (सोनू)

सिद्ध संत बाबा नीब करौरी महाराज (जिन्हें नीम करौली बाबा भी कहा जाता है) बीसवीं सदी के अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित संतों की श्रेणी में स्थान रखते हैं, जिन्होंने परब्रह्म से अति निकटता प्राप्त कर ली थी. बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम एवं हनुमानजी के परम उपासक थे. उन्होंने 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली श्री वृंदावन धाम में पूर्व नियोजित योजना के अनुरूप महासमाधि लेकर अपनी भौतिक लीलाओं को विराम दिया. इस प्रकार तिथि के हिसाब से आज 25 सितंबर को बाबा नीब करौरी महाराज का निर्वाणोत्सव उनके समाधि स्थल वृंदावन आश्रम में मनाया जा रहा है. बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों धूम मचा रही है. बाबा हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखा करते थे. संपूर्ण विश्व उनका घर था. सभी मनुष्य उनके बच्चे जैसे थे. बाबा नीब करौरी महाराज का जन्म सन् 1900 में उ.प्र. के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में मार्गशीर्ष माह की शुक्लपक्ष की अष्टमी को एक संपन्न जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था. बाबा नीब करौरी महाराज (पूर्व नाम पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा) के पिता दुर्गाप्रसाद एवं माता कौशल्यादेवी बहुत ही सरल, सहज एवं आस्थावान ब्राह्मण थे. बाबा की माता का निधन जब वे नौ वर्ष के थे तभी हो गया.

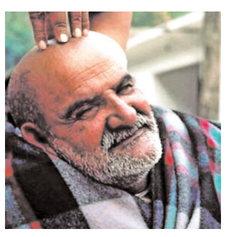

महाराजजी का विवाह ग्यारह वर्ष की उम्र में समीप के गांव की लक्ष्मी स्वरूपा रामबेटी के साथ हुआ. परंतु उनका मन तो प्रभु श्रीराम एवं हनुमानजी की भक्ति में ही लगा रहता था. उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिया. बाद में जब उनकी ख्याति उनके पिता ने भी सुनी और अपने पुत्र का पता जानने के उद्देश्य से बाबा के पास आए तो पुत्र को बाबा के रूप में देखकर वे हैरान हो गए. उन्होंने पुत्र को वैवाहिक और सांसारिक जीवन में लौटने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया. 1923 में वे अपने गांव अकबरपुर आ गए, और वहीं रहने लगे. इस बीच उनकी तीन संतानें हुईं. 1925 में बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा का जन्म हुआ. 1937 में छोटे बेटे धर्मनारायण शर्मा एवं 1945 में पुत्री गिरिजा देवी का जन्म हुआ. यद्यपि बाबा अपने जीवनकाल में कभी नागपुर नहीं आए, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री गिरिजा देवी के विवाह के लिए अपने गांव से सुदूर नागपुर में रहने वाले एक परिवार को चुना. उनकी पुत्री का विवाह हंसापुरी, नागपुर निवासी मथुराप्रसाद शर्मा (भटेले) एवं चमेली देवी के ज्येष्ठ पुत्र जगदीश प्रसाद भटेले से हुआ. बाबा के शरीर त्यागने के पश्चात बाबा की भतीजी कमला शर्मा का विवाह भी इसी परिवार के दूसरे पुत्र प्रा. अनिल शर्मा से हुआ. इस तरह नीब करौरी बाबा की दो बेटियां नागपुर के इस परिवार की बहुएं हैं.

आज का कार्टून

नकली व बेलगाम दवाओं के खिलाफ अब अदालत का ही आसरा

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जहां जन-कल्याण को शासन का मूलमंत्र माना जाता है, वहां स्वास्थ्य का क्षेत्र एक गंभीर संक्रमण काल से गुजर रहा है। बीमारियां जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उससे कहीं अधिक तेजी से चिकित्सा के नाम पर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ का एक भयावह और अनैतिक तंत्र विकसित हो चुका है। हाल ही में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मुनाफे की हवस और मरीजों के साथ हो रही धोखाधड़ी की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनाई दी है। न्याय के सर्वोच्च मंदिर ने दवा निर्माताओं, अस्पतालों और सरकारी नियामक संस्थाओं के रवैये पर जो तल्ख टिप्पणियां की हैं, उसने हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रयुक्त यह वाक्य- 'यह तो सीधे तौर पर दिन-दहाड़े डकैती है '– महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस लाचार भारतीय नागरिक की सामूहिक चीख का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीमारी से पहले इलाज के खर्च और उसमें होने वाली जालसाजी से मर जाता है।

अशोक भाटिया

न्यायालय के समक्ष जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। खासकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के घावों पर जिस तरह मुनाफाखोरी का नमक छिड़का जा रहा है, वह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि कैंसर की एक आवश्यक जीवन रक्षक दवा, जिसकी कीमत निर्माता कंपनी द्वारा रिटेलर के लिए महज ?2,700 तय की जाती है, उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य पूरे ?27,000 छाप दिया जाता है। यानी कि लागत और थोक मूल्य से ठीक दस गुना अधिक दाम पर उस दवा को बेचे जाने की खुली छूट दे दी गई। एक पीड़ित परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अकल्पनीय मूल्य अंतर पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि मरीजों को इस तरह बेदर्दी से लूटने की इजाजत व्यवस्था कैसे दे सकती है? निर्माता कंपनियां और बड़ी-बड़ी कॉरपोरेट फार्मेसियां मिलकर मरीजों की जेब पर जो डाका डाल रही हैं, उस पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी नियामक इकाइयां आंखें मूंदकर क्यों बैठी हैं?

यह मामला सिर्फ निजी क्षेत्र की लूट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और टैक्सपेयर्स के पैसे में सेंधमारी का भी एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। आज केंद्र सरकार 'आयुष्मान भारत', ष्टत्र॥स् और ष्टत्र॥स् जैसी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज का खर्च उठाती है। निजी अस्पताल इन्हीं बढ़ी हुई और मनमानी एमआरपी पर दवाएं खरीदते हैं और बाद में सरकारी खजाने से उसका शत-प्रतिशत रीइम्बर्समेंट क्लेम करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चंद दवा माफियाओं और निजी अस्पतालों की तिजोरियां भरने के लिए आम जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। करदाताओं का पैसा जो देश के बुनियादी ढांचे और लोक-कल्याण में लगना चाहिए था, वह दवा कंपनियों की साठगांठ की भेंट चढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाते हुए इसे 'स्पष्ट रूप से देश और जनता के साथ एक बड़ा फ्रॉड' करार दिया है। इस संदर्भ में एक अहम सुझाव यह भी आया कि क्यों न देश की सभी जीवन रक्षक दवाओं को एक एकीकृत मूल्य-नियंत्रण के दायरे में ला दिया जाए, जिससे जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का यह पूरा कृत्रिम भ्रम ही समाप्त हो जाए और दवाएं समान दाम पर उपलब्ध हो सकें।

एक तरफ जहां दवाओं के नाम पर यह संस्थागत और कानूनी लूट जारी है, वहीं दूसरी तरफ 'नकली दवाओं' का एक समानांतर और अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड चल रहा है, जो सीधे मौत का व्यापार कर रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में विशेष जांच दल और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी में एक बहुत बड़े अंतरराज्यीय नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वीरेश कुमार जैन नामक एक फार्मासिस्ट की मुख्य संलिप्तता वाले इस गिरोह ने करीब 90 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पतालों और क्लीनिकों में पिछले पांच वर्षों से नकली तथा एक्सपायर्ड हो चुकी कैंसर और आईसीयू दवाओं की धड़ल्ले से आपूर्ति की। ये अपराधी एक्सपायर हो चुकी दवाओं को दोबारा प्रोसेस करते थे, उन्हें चमचमाते नए डिब्बों में पैक करते थे, नामचीन अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय फार्मा ब्रांडों के नकली होलोग्राम और लेबल लगाते थे और अस्पतालों के परचेजिंग डिपार्टमेंट को आकर्षित करने के लिए पचास प्रतिशत तक के भारी डिस्काउंट का लालच देते थे। पांच साल तक, यानी कि 1,800 से अधिक दिनों तक अस्पतालों के खरीद तंत्र ने बिना किसी लैब टेस्टिंग या प्रामाणिकता की जांच किए, सिर्फ मुनाफे के लालच में इन नकली दवाओं को खरीदा और उन लाचार मरीजों के जिस्म में कीमोथेरेपी के नाम पर जहर के रूप में उतार दिया जो अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर वहां आए थे।

इस घिनौने अपराध की जद सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है; इसके तार कर्नाटक से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक फैले हुए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नकली दवाओं का नेटवर्क देशव्यापी नेटवर्क बन चुका है। कुछ समय पूर्व नागपुर के सरकारी अस्पताल में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां मरीजों को दी जाने वाली गोलियों में मुख्य औषधीय साल्ट की जगह साधारण टेलकम पाउडर भरा हुआ था। जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक या कैंसर रोधी दवाओं के नाम पर टेलकम पाउडर या चाक की गोलियां दी जाएंगी, तो उसका ठीक होना तो दूर, बीमारी और अधिक आक्रामक होकर उसकी जान ले लेगी। कानून के नजरिए से देखें तो यह धारा 302 यानी सीधे-सीधे हत्या का मामला बनता है, न कि केवल ट्रेडमार्क के उल्लंघन या मिलावट का। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में कहने को तो आजीवन कारावास और जब्त माल की कीमत का तीन गुना जुर्माने जैसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर अपराधियों को इसका कोई खौफ नजर नहीं आता। वजह साफ है–कमजोर लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपराधी अक्सर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपना वही खूनी कारोबार शुरू कर देते हैं।

यही कारण है कि देश की जनता और न्यायविदों को अब इस भयावह संकट से उबरने के लिए न्यायपालिका की ओर देखना पड़ रहा है। अब जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तो अदालती हस्तक्षेप ही एकमात्र उम्मीद बची है। अदालतों में दायर हालिया याचिकाओं में यह मांग बिल्कुल जायज है कि नकली और अत्यधिक महंगी दवाओं के मामलों की जांच के लिए तीन महीने की सख्त समय-सीमा तय हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक वर्ष के भीतर दोषियों को फांसी या उम्रकैद जैसी नजीर बनने वाली सजाएं दी जाएं। साथ ही, इस धंधे से अर्जित की गई अपराधियों और उनके परिवारों की पूरी चल-अचल संपत्ति को तुरंत कुर्क किया जाना चाहिए। दवा उद्योग को आत्ममंथन करना होगा कि जब आबकारी विभाग अपनी शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड और ट्रैक-एंड-ट्रेस मैकेनिज्म लागू करके एक-एक बूंद का हिसाब रख सकता है, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देश की जीवन रक्षक दवाओं के लिए वैसा ही अचूक और फुलप्रूफ डिजिटल बारकोडिंग सिस्टम देशव्यापी स्तर पर अनिवार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? शीर्ष 300 ब्रांडों पर क्यूआर कोड का नियम लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे देश की हर छोटी-बड़ी मेडिकल वाइल और टैबलेट स्ट्रिप पर अनिवार्य करना होगा।

दवाइयों के इस दोतरफा संकट–एक तरफ कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई बेलगाम कीमतें और दूसरी तरफ नकली दवाओं का जानलेवा जाल–ने चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता को भी दांव पर लगा दिया है। जब तक सरकारें राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगी और स्वास्थ्य को कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफे का जरिया बनने से नहीं रोकेंगी, तब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। फार्मा लॉबी की ताकत के आगे सरकारी अमले की कथित और रहस्यमयी चुप्पी इस बात का संकेत है कि बिना अदालती हंटर के यह तंत्र सुधरने वाला नहीं है। 2,700 की दवा को 27,000 में बेचना अगर डकैती है, तो नकली दवाएं बेचना सीधे-सीधे नरसंहार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीखें तय कर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत का यह सख्त रुख देश की नीति-नियंताओं की कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगा। देश को अब भाषणों और आश्वासनों की नहीं, बल्कि एक ऐसे कठोर कानून और पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जरूरत है, जहां किसी भी मां, बहन या पिता को पैसे के अभाव में या नकली दवा के जहर के कारण तड़प-तड़प कर दम न तोड़ना पड़े। स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे मुनाफाखोरों की मंडी बनने से बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है।

अमेरिकी धरती पर खड़े होकर ट्रंप को घेरना आसान नहीं...

संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन में इस बार एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। अमेरिकी धरती न्यूयॉर्क पर खड़े होकर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह अमेरिका की नीतियों को ही आड़े हाथ लिया, उससे वैश्विक राजनीति में बढ़ती बेचैनी साफ दिखाई दी। ईरान ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी, फ्रांस ने महाशक्तियों के तकनीकी और सामरिक वर्चस्व पर सवाल उठाए, सीरिया ने गोलान पहाड़ियों पर अमेरिकी नीति को खारिज किया, जबकि ब्राजील और तुर्किये जैसे देशों ने संप्रभुता, विदेशी हस्तक्षेप और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। संदेश साफ है कि दुनिया की अनेक सरकारें मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकटों के लिए अमेरिकी नीतियों और व्यापक शक्ति आधारित राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए अब ज्यादा मुखर दिखाई दे रही हैं।

नीरज कुमार दुबे

इस पूरे घटनाक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भाषण बेहद महत्वपूर्ण रहा। 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में मैक्रों ने चेतावनी दी कि दुनिया कहीं फिर से 'जंगल के कानून' की ओर न लौट जाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उस समय कमजोर होती है जब ताकतवर देश नियमों और संस्थाओं से ऊपर खुद को समझने लगते हैं। मैक्रों ने सबसे तीखा सवाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य को लेकर उठाया। उनका कहना था कि दुनिया का भविष्य केवल अमेरिका, चीन या कुछ बड़ी निजी कंपनियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने तकनीकी संप्रभुता, ओपन सोर्स अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों और रक्षा, साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। गाजा के मुद्दे पर भी मैक्रों ने पश्चिमी देशों की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने गाजा की मानवीय स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए मौजूदा शांति प्रयासों पर सवाल उठाया। पश्चिमी तट में बस्तियों से जुड़ी हिंसा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन इजराइल के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकता। यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने नागरिक और ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने तथा काला सागर से अनाज परिवहन की सुरक्षा के लिए दोहरी अस्थायी युद्धविराम व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा।

लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को सबसे सीधी चुनौती ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की ओर से मिली। 23 सितंबर को पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन पहले दिए गए कड़े बयान का जवाब देते हुए कहा कि ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ईरान को आतंकवाद का दोषी नहीं, बल्कि आतंकवाद का पीड़ित बताया।

पेजेशकियन ने ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव को लेकर कहा कि उनका देश 'घुटने नहीं टेकेगा।' उन्होंने परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा से इंकार किया, लेकिन शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक, विशेषकर चिकित्सा और कृषि के लिए, इन पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार करने से भी साफ इंकार कर दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी उन्होंने ईरान के नौवहन अधिकारों पर जोर दिया और अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त करने की मांग रखी।

हालांकि ईरानी राष्ट्रपति ने युद्ध के बीच कूटनीति का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत संभव है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को धमकी, बल प्रयोग और प्रतिबंधों की भाषा छोड़नी होगी। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच कतर की मध्यस्थता से अप्रत्यक्ष बातचीत भी हुई, लेकिन तत्काल कोई बड़ी सफलता सामने नहीं आई। ईरानी पक्ष आर्थिक और समुद्री प्रतिबंध हटाने तथा फ्रीज हुए धन से जुड़े मुद्दों पर अपनी शर्तों पर कायम रहा।

इस टकराव का सबसे नाटकीय दृश्य तब देखने को मिला जब पेजेशकियन के भाषण के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा कक्ष से बाहर चला गया। एक ओर मंच पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे रहा था, दूसरी ओर पर्दे के पीछे दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी चल रही थी। यानी युद्ध और कूटनीति एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए।

वहीं सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने भी अमेरिकी नीति पर खुला प्रहार किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कहा कि गोलान पहाड़ियां सीरिया की भूमि हैं और किसी भी बाहरी शक्ति को सीरियाई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपने का अधिकार नहीं है। उनका यह बयान अमेरिका द्वारा गोलान पहाड़ियों पर इजराइली संप्रभुता को मान्यता देने वाली नीति के सीधे विरोध में था। साथ ही अल-शरा ने इजराइली सैन्य कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए सैकड़ों हवाई हमलों, बड़ी संख्या में घुसपैठ और गिरफ्तारियों का आरोप लगाया तथा इजराइली सेना की वापसी और 1974 के अलगाव समझौते के पालन की मांग की। साथ ही उन्होंने युद्ध के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने सरकारी संस्थाओं को स्थिर करने, हथियारों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में लाने, संक्रमणकालीन न्याय लागू करने और मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की बात भी कही। उधर, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भी विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता के सवाल को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील किसी बाहरी शक्ति का पिछलग्गू नहीं है और विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने भी संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था और सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पर सवाल उठाए तथा गाजा के मुद्दे पर इजराइल को मिल रहे समर्थन की आलोचना की। देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम को केवल अमेरिका-विरोधी भाषणों की श्रृंखला नहीं माना जा सकता। असली मुद्दा तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था का है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अलग-अलग देशों की आवाजें यह सवाल उठा रही हैं कि क्या सैन्य ताकत, आर्थिक प्रतिबंध, तकनीकी वर्चस्व और कूटनीतिक दबाव के दम पर विश्व व्यवस्था चलाई जा सकती है।

न्यूयॉर्क में इस बार अमेरिका के सामने सवाल केवल ईरान का नहीं था। सवाल यह था कि क्या दुनिया कुछ शक्तिशाली देशों और बड़ी तकनीकी कंपनियों के निर्णयों से चलेगी या फिर संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका दोबारा मजबूत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह अधिवेशन इसी टकराव को बेहद तीखे ढंग से दुनिया के सामने रख रहा है।

संक्षिप्त समाचार

एशियन गेम्स

नेपाल ने अफगानिस्तान को 16 गेंद पहले 5 विकेट से हराया

द्वनिशिन । एशियन गेम्स 2026 में शुक्रवार को कोरोगी स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में नेपाल क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत खराब रही और टॉप-3 बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। पारी की शुरुआत करने आए मोहम्मद अकरम 2 रन और हसन ईसाखिल बिना खाता खोले आउट हो गए। करीम जन्नत 9 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे

नंबर पर बल्लेबाजी के लिए फैसल शिलोजादा और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नजबुल्ला जादरान ने टीम को संभाला। दोनों ने 30-30 रन की पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए नांगेयालिया खरोटी ने भी नाबाद 17 रन बनाए।

नेपाल की तरफ से ललित राजवंशी ने 3 और कुशाल भुर्टेल ने 4 विकेट लिए।

103 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने 12 के स्कोर पर 2 और 31 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन संदीप जोरा के 35 गेंदों पर बनाए 34 रन और पूर्व कप्तान रोहित पौडेल के 32 गेंदों पर बनाए नाबाद 33 रनों की बदौलत टीम ने 17.2 ओवर में 5 विकेट पर 103 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी 15 रन बनाए। नेपाल का अगला मैच शनिवार को जापान से होना है। इस मैच में जीत की स्थिति में नेपाल ग्रुप में शीर्ष

50 मीटर राइफल 3पी टीम सिल्वर के बाद ऐश्वर्य, नीरज व्यक्तिगत मेडल से चूके

नागोया । भारतीय राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार शुक्रवार को यहां ऐची प्रीफ. जनरल शूटिंग गैलरी में पुरुषों के 50 मीटर 3-पोजीशन इवेंट के फाइनल में मेडल से चूक गए। वे क्रमश: पांचवें और आठवें स्थान पर रहे। ऐश्वर्य 327.6 के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जबकि नीरज 299.0 के साथ आठवें स्थान पर रहे। चीन के युकुन लियू ने 360.5 के गेम्स-रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड जीता, जबकि झांग चांगहोंग ने 360.2 के साथ सिल्वर जीता। इस्लाम सतपायेव ने 348.3

के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐश्वर्य शुरुआती स्टेज में रेस में बने रहे, प्रोन सीरीज के बाद छठे स्थान पर रहे, फिर दूसरी नीलिंग सीरीज के बाद 205.3 के साथ पांचवें स्थान पर पहुंचे और आखिर में ओवरऑल पांचवें स्थान पर रहे। नीरज का फाइनल ज्यादा मुश्किल साबित हुआ और वह 299 के स्कोर के साथ आठ फाइनलिस्ट में सबसे आखिर में रहे। ऐश्वर्य हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन गेम्स में भारत के सबसे सफल शूटर्स में से एक थे। उन्होंने चार पदक जीते थे। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन टीम इवेंट्स में गोल्ड और 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत ब्रॉन्ज और 50 मीटर राइफल 3-पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता था।

एशियन गेम्स: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में

सुरुचि, कमलजीत ने गोल्ड जीता

नागोया । भारत को एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड मिल गया है। सुरुचि इंदर सिंह और कमलजीत ने एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने मिलकर फाइनल में 484.6 का एशियन रिकॉर्ड स्कोर बनाया। भारतीय जोड़ी ने दबाव वाले फाइनल में हिम्मत नहीं हारी और सटीकता के साथ लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्टैंडिंग में टॉप पर रही। दक्षिण कोरिया के सुहयोन होंग और गेउन चू ने 478.0 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि ईरान के वाहिद गोलखंडन और हानियेह रोस्तमियान ने 415.8 के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडोनेशिया के डार्मोयो ए. और प्रबोवो एम. 349.4 के साथ चौथे स्थान पर रहे। सुरुचि और कमलजीत ज्यादातर कॉम्पिटिशन में नियंत्रण में थे, और दबाव बढ़ने पर भी उन्होंने अपना कंपोज़र बनाए रखा। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भारतीय जोड़ी शांत रही और अपनी बढ़त बनाने और उसे बचाने के लिए कई सटीक शॉट लगाए। मिक्स्ड-टीम फॉर्मेट में उनकी पार्टनरशिप बहुत जरूरी साबित हुई। उनका शानदार स्कोर आखिरकार रिपब्लिक ऑफ कोरिया को पीछे रखने के लिए काफी साबित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जैसे ही फाइनल स्कोर आए, 484.6 के एशियन रिकॉर्ड ने भारत की यादगार जीत पक्की कर दी और शूटिंग टीम को नागोया में जश्न मनाने का एक और कारण दे दिया। इस गोल्ड ने कॉन्टिनेंटल लेवल पर शूटिंग में देश की लगातार मजबूती को दिखाया। सुरुचि और कमलजीत के लिए यह पल सिर्फ पोडियम पर सबसे ऊपर खड़े होने से कहीं ज्यादा था। उनके 484.6-पॉइंट के प्रयास ने एशियन रिकॉर्ड बुक में फिर से नाम लिख दिया। इससे पहले, भारतीय जोड़ी ने 587 (29 इनर 10) के स्कोर के साथ एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड तोड़ा, और हांगझोऊ 2023 में एक और भारतीय जोड़ी, सरबजोत सिंह और दिव्या सुब्बाराजू के बनाए 577 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

राजू, थेन्नारासु, रामराज और मनु की चौकड़ी ने देश को दिलाया रजत, पीएम मोदी ने दी बधाई

नागोया । माचेट्टीरा पूवम्मा राजू, विशाल थेन्नारासु, विथ्या रामराज और थेक्किनालिल मनु की भारतीय चौकड़ी ने नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुए कड़े मुकाबले वाले फाइनल में 4×400 मीटर में 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला। भारतीय रिले टीम की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएमओ ने एक्स पर पीएम मोदी के हवाले से लिखा, 'हमारी मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम का शानदार प्रदर्शन। मनु टीएस, पूवम्मा एमआर, विशाल टीके और विथ्या रामराज को एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। उनकी गति, तालमेल और पक्के इरादे ने रेस को रोमांचक बना दिया और भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का पल बना। उम्मीद है कि वे और भी ऊंचाइयों को छूते रहेंगे।' प्रतियोगिता में बहरीन ने 3:12.87 के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण जीता, जबकि वियतनाम 3:14.54 में रेस पूरी करके तीसरे नंबर पर रहा और ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान 3:15.52 के साथ चौथे स्थान पर रहा।

एशियन गेम्स

भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

मेजबान जापान को 3-1 से हराया

नागोया । एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूल बी के मैच में मेजबान जापान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त बना ली थी। पहले क्वार्टर में लालरेम्सियामी ने ओपन प्ले से गोल करके स्कोरिंग की शुरुआत की, जिसके बाद दूसरे क्वार्टर के आखिर में इशिका ने गोल किया। पहले हाफ में जापान भारत के ज्यादातर अटैक को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन भारत ने स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर मिले मौकों का फायदा उठाकर नियंत्रण बनाए रखा। तीसरे क्वार्टर में, भारत ने

अपनी बढ़त 3-0 कर ली, जब नवनीत कौर ने सर्कल के अंदर बॉल ली, दाईं ओर मुड़ीं और जापानी गोलकीपर के ऊपर से उसे दूर कोने में डाल दिया। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में जापान की कोबायाकावा शिहो ने टीम के लिए एकमात्र गोल किया। भारत ने अपनी बढ़त बनाए रखते हुए 3-1 से जीत हासिल की। भारतीय टीम की यह लगातार चौथी जीत थी। हॉकी के अलावा शुक्रवार का दिन भारत के लिए शूटिंग की वजह से भी अच्छा रहा। भारत को शूटिंग में एक गोल्ड और एक रजत पदक मिले हैं। भारत के लिए सुरुचि इंदर सिंह और कमलजीत ने एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने मिलकर फाइनल में 484.6 का एशियाई रिकॉर्ड स्कोर बनाया। भारतीय जोड़ी ने दबाव वाले फाइनल में हिम्मत नहीं हारी और सटीकता के साथ लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्टैंडिंग में टॉप पर रही। दक्षिण कोरिया के सुहयोन होंग और गेउन चू ने 478.0 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि ईरान के वाहिद गोलखंडन और हानियेह रोस्तमियान ने 415.8 के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पुरुष कबड्डी में थाईलैंड को हराकर फाइनल में भारत

तोकाई । भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने शुक्रवार को तोकाई सिटीजन जिमनैजियम में सेमीफाइनल में थाईलैंड को 66-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आठ बार की विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम पुरुषों की स्पर्धा के नौवें फाइनल में पहुंच गई है और अपने 2023 के टाइटल को बचाने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दोनों हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 66-28 से हरा दिया। भारत ने पहले हाफ में 37 पॉइंट्स लिए, जबकि थाईलैंड सिर्फ 18 पॉइंट्स ही बना पाया। दूसरा हाफ भी भारतीय टीम के लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसने 29 पॉइंट्स लिए, जबकि थाईलैंड ने 10 पॉइंट्स लिए।

भारतीय टीम ने पहले हाफ में 21 आउट लिए, जबकि उसने थाईलैंड के डिफेंस में भी गहरी पैठ बनाकर 12 बोनस पॉइंट्स लिए और दो ऑल आउट किए। उसके अपोनेंट्स ने पहले हाफ के शुरुआती हिस्से में उसे कड़ी टक्कर दी और 13 आउट, तीन बोनस पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब रहे तथा एक ऑल आउट भी किया। वहीं, दूसरे हाफ में भारत ने 22 और आउट लिए और तीन बोनस पॉइंट्स हासिल किए, साथ ही दो ऑल आउट भी किए, जबकि थाईलैंड ने सात आउट पॉइंट्स, दो बोनस पॉइंट्स हासिल किए और एक टेक्निकल पॉइंट भी लिया।

भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है। फाइनल में टीम इंडिया का सामना ईरान या चीनी ताइपे से होगा।

इससे पहले, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी नेपाल पर 48-24 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाया था। टीम ने पहले हाफ में 31 पॉइंट्स हासिल किए और ब्रेक तक 31-17 की मजबूत लीड ले ली। फिर भारत ने दूसरे हाफ में 17 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि नेपाल को सिर्फ सात पॉइंट्स मिले।

भारतीय टीम रेडिंग और डिफेंस दोनों में बेहतर थी। पहले हाफ में टीम इंडिया ने 23 आउट पॉइंट्स, चार बोनस पॉइंट्स लिए और दो ऑल आउट किए। दूसरी तरफ, नेपाल को 13 आउट पॉइंट्स और तीन बोनस पॉइंट्स मिले तथा उसने एक सुपर टैकल किया।

महिला कबड्डी टीम ने नेपाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई

नागोया । भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर एशियन गेम्स 2026 के महिला कबड्डी फाइनल में जगह बना ली है। इवेंट में जोरदार प्रदर्शन कर रही भारतीय टीम ने इस मैच की शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में की और पहले पांच मिनट में ही असरदार रेड से पॉइंट्स जमा करके 9-5 की लीड ले ली। नेपाल ने भारतीय रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाया, जिसमें इंडियन रेडर सोनाली पर एक सुपर टैकल भी शामिल था, जिससे वह लाइन तक नहीं पहुंच पाईं। इसके बावजूद, इंडिया ने 15-10 की पांच पॉइंट्स की मामूली लीड बनाए रखी। नेपाल की गंगा घिमिरे ने एक शानदार रेड की, एंकल होल्ड के बावजूद चार पॉइंट्स कमाए, जिसकी पुष्टि एक लंबे रिव्यू के बाद हुई। इससे पहले हाफ में चार मिनट बाकी रहते अंतर 21-15 हो गया। हालांकि, इंडिया ने धीरे-धीरे अपनी बढ़त बढ़ाई, और हाफ टाइम तक 31-17 की बड़ी लीड ले ली। इस दौरान संजू देवी और सोनाली का प्रदर्शन दमदार रहा।

दूसरे हाफ में भी भारत ने बढ़त बनाए रखी और 48-24 से बड़ी जीत हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला शनिवार को चीनी ताइपे या ईरान से होगा। भारतीय टीम गत चैंपियन है। ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में एक बार फिर से अपना ताज बचाने उतरेगी। शुक्रवार का दिन भारतीय टीम के लिए अच्छा रहा। कबड्डी के साथ ही शूटिंग, हॉकी, रिले टीम और स्क्वैश में शानदार प्रदर्शन किया।

नंदिनी शर्मा बोली- जब हम पोडियम पर खड़े थे और राष्ट्रगान बजा

...तो वह एहसास बिल्कुल अलग था

चंडीगढ़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे पहले, भारत ने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भी महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। दाएं हाथ की गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। एशियन गेम्स में सोने का तमगा हासिल करने के बाद नंदिनी शर्मा ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में कहा, 'यह एशिया कप के फाइनल मैच की बात है। तब मुझे बेस्ट फील्डिंग के लिए मेडल मिला था। बेस्ट फील्डिंग के लिए मेडल मिलने का एहसास मेरे लिए बहुत ही शानदार था। बहुत अच्छा लगा था।' बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 3 विकेट हासिल करने वालीं नंदिनी शर्मा ने कहा, 'हमें बस अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है। नतीजा चाहे जो भी हो, हमें बस अपना बेस्ट खेलना

है। अब तक आप जो अच्छा करते आ रहे हैं, उसे जारी रखना है। स्मृति दी (स्मृति मंधाना), जेमी (जेमिमा रोड्रिगेज) मुझे काफी सपोर्ट करती हैं। विमेंस प्रीमियर लीग में जेमी के अधीन मेरा करियर शुरू हुआ था। वहां से मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि जेमी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्मृति दी, हमेशा की तरह, हर बार मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरा साथ देती हैं और मुझे समझाती हैं कि क्या करना है। '

एशियन गेम्स 2026 में अब तक भारत को एकमात्र गोल्ड हाथ लगा है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दिलाया। नंदिनी ने कहा, 'भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाना बहुत गर्व की बात है। यह एहसास अद्भुत है। जब हम पोडियम पर खड़े थे और राष्ट्रगान बज रहा था, तो वह एहसास बिल्कुल अलग था, खासकर तब जब हमारा तिरंगा सबसे ऊपर था। यह सच में बहुत शानदार लगा। '

पहला वनडे: ब्रीत्जके का 'शतक', केशव ने लगाया 'चौका'

अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से धूल चटाई

डरबन। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किंग्समीड में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच को 67 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। गुरुवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 297 रन बनाए। इस टीम ने 29 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद मैथ्यू ब्रीत्जके ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। बावुमा 48 गेंदों में 4 चौकों के साथ 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ब्रीत्जके ने रयान रिकेल्टन के साथ चौथ विकेट के लिए 42 रन और डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 168 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

रिकेल्टन 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे,

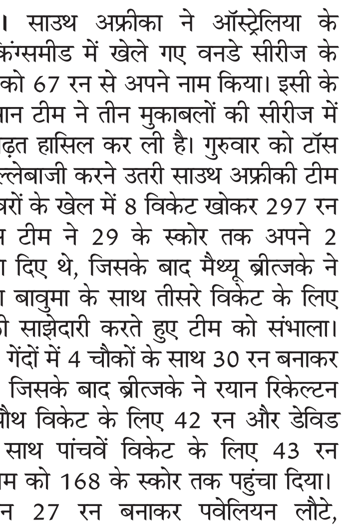

जबकि मिलर ने टीम के खाते में सिर्फ 9 रन जुटाए। इसके बाद ब्रीत्जके ने मार्को जानसेन के साथ छठे विकेट के लिए 81 गेंदों में 107 रन की साझेदारी की। ब्रीत्जके 14 चौकों और 2 छक्कों के साथ 112 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जानसेन ने 59 गेंदों में 75 रन कूटे। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल रहे। विपक्षी खेमे से नाथन एलिस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि एडम जांपा को 2 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, जोश हेजलवुड ने 1 विकेट अपने नाम किया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.2 ओवरों में 230 के स्कोर पर सिमट गई। कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर मेबमानों को मजबूत शुरुआत दिलाई। इस सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 90 रन की साझेदारी की। मार्श 36 गेंदों में 6 छक्कों और 5 चौकों के साथ 60 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए त्राधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यालय नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेल: alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670